वर्ष 12 • अंक 276 • 12 पृष्ठ • मूल्य 5 रुपये

मंगलवार 7 जनवरी 2020

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

▶▶ पृष्ठ 6

बारिश ने बढ़ाया रबी फसलों का रकबा

नरेंद्र मोदी ▶▶ पृष्ठ 12

भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मुहिम उद्योग पर हमला नहीं

डॉलर रु. 71.90 ▲ 10 पैसे | यूरो रु. 80.60 ▲ 70 पैसे | सोना (10ग्राम) रु 40678 ▲ 747 रुपये | सेंसेक्स 40676.60 ▼ 788.00 | निफ्टी 11993.00 ▼ 233.60 | निफ्टी फ्यूचर्स 12043.70 ▲ 50.70 | ब्रेंट क्रूड 69.90 डॉलर ▲ 0.90 डॉलर

एक नज़र

दिल्ली में विधानसभा चुनाव 8 फरवरी को

दिल्ली की 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए 8 फरवरी को मतदान होगा जबकि मतगणना 11 फरवरी को होगी। चुनाव आयोग ने सोमवार को चुनाव तारीखों की घोषणा की। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि चुनावों की अधिसूचना 14 जनवरी को जारी होगी जबकि नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 24 जनवरी होगी। इन चुनावों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप), भाजपा और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबले होने की संभावना है। 2015 में हुए पिछले विधानसभा चुनावों में आप ने 67 सीटें जीती थीं जबकि भाजपा को केवल तीन सीटें मिली थीं।

शिवालिक मर्केंटाइल के लघु वित्त बैंक बनने को मंजूरी

आरबीआई के शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के बारे में दिशानिर्देशों का मसौदा जारी करने के एक पखवाड़े के भीतर उत्तर प्रदेश की शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को लघु वित्त बैंक बनने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। इस बैंक का कारोबार कई राज्यों में फैला है। आरबीआई के दिशानिर्देशों के मुताबिक यूसीबी को अपनी कुल उधारी का 75 फीसदी हिस्सा प्राथमिकता वाले क्षेत्र को देना होगा। आरबीआई सितंबर, 2018 में यूसीबी को लघु वित्त बैंक बनाने की स्वैच्छिक योजना लाया था लेकिन इसे कोई भाव नहीं मिला। लेकिन पीएमसी घोटाला सामने आने के बाद केंद्रीय बैंक ने यूसीबी के लिए नियमों को सख्त बनाने की कवायद शुरू कर दी है।

एसी में होगा 24 डिग्री सेल्सियस डिफॉल्ट तापमान

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने सोमवार को कहा कि सभी रूम एयर कंडीशनरों में डिफॉल्ट रूम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसका मतलब है कि जब एसी को ऑन किया जाएगा तो यह 24 डिग्री सेल्सियस पर चालू होगा। केंद्र सरकार ने बीईई के साथ सलाह मशविरे के बाद 30 अक्टूबर को रूम एसी के लिए नए ऊर्जा प्रदर्शन मानक अधिसूचित किए थे। इसके मुताबिक 1 जनवरी, 2020 से देश में सभी तरह के रूम ऐसी की डिफॉल्ट सेटिंग 24 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। इसके कारण एसी की कीमत 8 से 13 फीसदी तक बढ़ सकती है।

आरइन्फ्रा ने की 1048 करोड़ रु. के भुगतान में चूक

वित्तीय संकट से जूझ रही रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर ने दिसंबर 2019 में समाप्त तिमाही में कुल 1048.70 करोड़ रुपये के भुगतान की चूक की। कंपनी ने सोमवार को एनएसई को यह जानकारी दी। इस चूक का कारण ऋण और बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से नकद क्रेडिट जैसी सुविधाओं से संबंधित है। पिछले साल जुलाई में उसने ऋणदाताओं के साथ अंतर-ऋणदाता करार किया था जिससे उसे छह महीने की मोहलत मिल गई थी। पृष्ठ 2

आज का सवाल

क्या 'निर्विक' योजना से सुगम होगी निर्यात की राह

www.bshindi.com **पर राय भेजें।**
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या अमेरिकी-ईरान तनाव भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ाएगा मुश्किलें?	हां	76.47%
	नहीं	23.53%

तेल की तपिश से बाजार परेशान

अमेरिका-ईरान में तनाव बढ़ने से निवेशकों में घबराहट

सुंदर सेतुरामन
मुंबई, 6 जनवरी

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने के कारण कच्चे तेल के दाम बढ़ने और रुपये तथा राजकोषीय घाटे पर इसका असर पड़ने की आशंका से शेयर बाजार में आज तेज गिरावट दर्ज की गई। बेंचमार्क सूचकांकों- सेंसेक्स और निफ्टी में 1.9 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई जो 3 सितंगर, 2019 के बाद एक दिन में आई सबसे बड़ी गिरावट है। सेंसेक्स 788 अंक लुढ़ककर 40,677 पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 231 अंक के नुकसान के साथ 11,996 पर बंद हुआ।

पिछले हफ्ते इराक में ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद पश्चिम एशिया में सैन्य संघर्ष का खतरा बढ़ गया है। ईरान ने रविवार को घोषणा की कि उसने यूरेनियम संग्रहण की सीमा का अनुपालन नहीं करने का निर्णय किया है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी ठिकानों पर हमले होते हैं तो वह भी ईरान को मुंहतोड़ जवाब देंगे। विश्लेषकों का कहना है कि भू-राजनीतिक तनाव ने अज्ञात जोखिम बढ़ा दिया है जिसका भारतीय बाजार पर भी असर पड़ रहा है।

मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के संस्थापक सौरभ मुखर्जी ने कहा, 'कच्चे तेल के दाम बढ़ने से हमारा व्यापार घाटा और बढ़ेगा तथा कमजोर वृद्धि वाले माहौल में कच्चे तेल के ऊंचे दाम से आर्थिक सुधार की गति और प्रभावित होगी। अगर भू-राजनीतिक तनाव लंबा खिंचता है तो इक्विटी निवेशकों की धारणा भी प्रभावित होगी और भारत में विदेशी निवेश पर असर पड़ सकता है।'

कच्चे तेल में 10 डॉलर का इजाफा होने से भारत का आयात बिल प्रति महीना करीब 1.5 अरब डॉलर बढ़ सकता है और मुख्य मुद्रास्फीति 0.4 फीसदी बढ़ सकती है। शुक्रवार को ब्रेंट क्रूड 3.5 फीसदी बढ़कर 68.96 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ था।

डॉलर के मुकाबले रुपया भी 8.18 फीसदी नरम होकर कारोबार के दौरान 72 के स्तर को पार कर गया था। हालांकि कारोबार की समाप्ति पर रुपया 71.94 पर बंद हुआ। अमेरिका-ईरान के तनाव से नए साल की शुरुआत में शेयरों को लेकर लगाए गए सकारात्मक अनुमान पर भी संदेह खड़ा हो सकता है। अमेरिका और चीन के बीच पहले चरण का व्यापार सौदे पर इस माह के अंत तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद है। संबंधित खबर : पृष्ठ 3

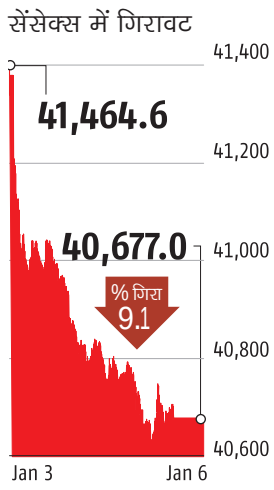

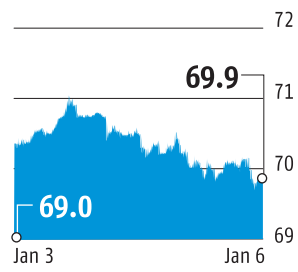

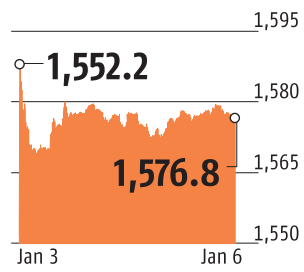

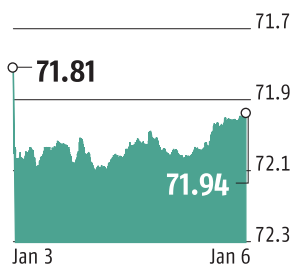

सीसीबी की समय सीमा नहीं बढ़ाएगा आरबीआई!

रघु मोहन
नई दिल्ली, 6 जनवरी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) पूंजी संरक्षण कोष (कैपिटल कंजर्वेशन बफर या सीसीबी) का अनुपालन करने के लिए बैंकों को दी समय सीमा नहीं बढ़ा सकता है। आरबीआई ने पिछले साल बैंकों को वित्त वर्ष 2020 के अंत तक 2.5 प्रतिशत सीसीबी रखने की शर्त पूरी करने का निर्देश दिया था। केंद्र को वित्त वर्ष 2021 में बैंकों को पूंजी मुहैया करते वक्त इस पहलू का ध्यान जरूर रखना होगा।

सीसीबी वह रकम होती है, जिसका प्रावधान बैंकों को मुश्किल हालात से निपटने के लिए रखना होता है। इस प्रावधान की शुरुआत 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद हुई थी। सीसीबी की अतिरिक्त 0.625 प्रतिशत किस्त टलने से बैंकों के पास 37,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त रकम बच गई थी। इस वजह से बैंकों को 3.5 लाख करोड़ रुपये तक के ऋण आवंटित करने में मदद मिली होगी। हालांकि वित्त वर्ष 2021 में बैंकों को यह सुविधा नहीं मिलेगी जब तक उन्हें सरकार की तरफ से पर्याप्त पूंजी नहीं मिलेगी।

सीसीबी पर बैंकों की सुस्त चाल से 1 अप्रैल 2013 से पूंजी अनुपात का क्रम टूट गया था। केंद्रीय बैंक और वित्त मंत्रालय के बीच बजट पूर्व बातचीत में इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। यह विषय आरबीआई के 7 जून के उस परिपत्र से भी जुड़ा है, जिसमें बैंकों को अधिक प्रावधान करने के लिए कहा गया है। दूरसंचार कंपनियों को केंद्र को ब्याज सहित 1.333 लाख करोड़ रुपये भुगतान करने संबंधी उच्चतम न्यायालय का आदेश भी इस विषय से संबद्ध है। केंद्रीय बैंक ने ट्रेंड ऐंड प्राग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया (2017-18) पर अपनी रिपोर्ट में सीसीबी के संबंध में बैंकों को ढील दिए जाने का खास जिक्र किया था। (शेष पृष्ठ 3 पर)

पूंजी का गणित

जोखिम भारांश वाली संपत्तियों के प्रतिशत में नियामकीय पूंजी

न्यूनतम साझा इक्विटी टीयर 1 (सीईटी 1) अनुपात	5.5
कैपिटल कंजर्वेशन बफर (साझा पूंजी शामिल)	2.5
सीईटी 1 अनुपात और कैपिटल कंजर्वेशन बफर	8.0
अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी	1.5
न्यूनतम टीयर कैपिटल अनुपात	7.0
टीयर 2 पूंजी	2.0
न्यूनतम कुल पूंजी अनुपात	9.0

मूल समयसीमा

कैपिटल कंजर्वेशन अनुपात (जोखिम-भारांश संपत्ति का %)

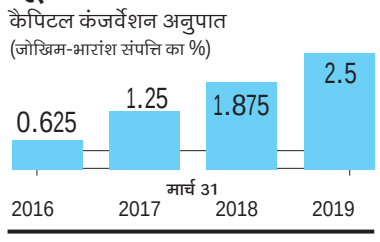

कंपनी पंजीयक की याचिका खारिज

रुचिका चित्रवंशी
नई दिल्ली, 6 जनवरी

- **टाटा संस-मिस्त्री मामले में एलसीएलएटी ने खारिज की कंपनी पंजीयक मुंबई की याचिका**
- **कंपनी का दर्जा पब्लिक से प्राइवेट में बदलने का है मामला**
- **आदेश से 'गैर कानूनी' और 'कंपनी पंजीयक की मदद से' जैसे शब्द हटाने की मांग**

टाटा संस-साइरस मिस्त्री मामले में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील पंचाट (एनसीएलएटी) ने कंपनी पंजीयक, मुंबई की याचिका को खारिज कर दिया। कंपनी पंजीयक ने अपनी याचिका में टाटा संस-साइरस मिस्त्री मामले में पहले के आदेश में संशोधन की मांग की थी और कहा कि इसमें कंपनी पंजीयक की कोई दुर्भावनापूर्ण मंशा नहीं थी।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के आधार पर ही सरकार इस मामले में कोई कदम उठाएगी। उन्होंने कहा, 'अपील पंचाट कानून की व्याख्या करने के लिए स्वतंत्र है। हम अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं क्योंकि सरकारी संस्था के बारे में इसमें टिप्पणी की गई है। हम इस मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेश का इंतजार करेंगे।'

एनसीएलएटी ने अपने आदेश में कहा है, 'हमने पाया कि कंपनी पंजीयक ने इसे गलत तरीके से लिया है क्योंकि कंपनी पंजीयक मुंबई के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की गई है और न ही उनके खिलाफ कोई आरोप लगाए गए हैं।'

कंपनी पंजीयक मुंबई ने टाटा संस को पब्लिक से प्राइवेट कंपनी में बदलने से संबंधित पंचाट के आदेश से 'गैर कानूनी' और 'कंपनी पंजीयक की मदद से' जैसे शब्द हटाने की मांग की थी। 18 दिसंबर को अपने आदेश में एनसीएलएटी ने कहा था कि टाटा संस ने कंपनी पंजीयक की मदद से कंपनी का दर्जा पब्लिक से प्राइवेट में बदलने में जल्दबाजी दिखाई, जो गैर-कानूनी था। टाटा संस के मानद चेयरमैन रतन टाटा और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसे ने एनसीएलएटी के आदेश को अलग से उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है।

न्यायाधीश एसजे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाले दो जजों के पीठ ने कहा कि आदेश में कंपनी और उसके निदेशक मंडल को संदर्भित किया है न कि कंपनी पंजीयक को। उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी का दर्जा बदलने के आदेश कंपनी पंजीयक के खिलाफ नहीं है।

कंपनी पंजीयक ने पंचाट को बताया कि कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2000 के अनुसार धारा 43 ए (2ए) के तहत पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में बदलने का अधिकार दिया गया है। एनसीएलएटी ने उल्लेख किया कि टाटा संस ने 19 जुलाई, 2018 को अपने पत्र में कंपनी पंजीयक को बताया कि वह धारा 34ए (2ए) का इस्तेमाल कर कंपनी का दर्जा बदल रही है, ऐसे में कंपनी पंजीयक के पास इस बदलाव की अनुमति देने की संवैधानिक बाध्यता थी।

हालांकि न्यायाधीश ने कहा कि कंपनी पंजीयक ने अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान को नहीं देखा जिसमें कंपनी द्वारा दर्जा बदलने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी की जरूरत होती है।

टाटा समूह के वकीलों ने कहा कि एनसीएलएटी के आदेश ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत गठित कंपनी की वैधता और अस्तित्व पर संकट की तरह है। उन्होंने कहा कि आज के आदेश में भी वर्ष 2000 में खत्म की गई धारा 43ए की उप-धारा (4) को ध्यान में नहीं रखा गया। अभी केवल 43ए की उप-धारा (2ए) ही प्रभावी है। टाटा संस ने इसी धारा के तहत कंपनी पंजीयक के पास आवेदन किया था। लेकिन एनसीएलएटी ने इसकी अनदेखी की।

अक्षय ऊर्जा फर्मों के शुल्क बोझ से एनबीएफसी पर दबाव : बुनियादी ढांचा वित्त कंपनियों को अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में लगी पूंजी से संपत्ति गुणवत्ता पर पड़ने वाले अतिरिक्त दबाव का सामना करना पड़ सकता है। इन परियोजनाओं पर शुल्क जोखिम की तलवार लटक रही है। पृष्ठ 4

'निर्विक' से मिलेगा देश के निर्यात को दम

दिलाशा सेठ और शुभायन चक्रवर्ती
नई दिल्ली, 6 जनवरी

सरकार निर्यात में गिरावट को रोकने के लिए अगले कुछ हफ्तों में निर्यात वित्त योजना लाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत छोटे कारोबारियों को रुपये और डॉलर के लिहाज से कम ब्याज दर की पेशकश की जाएगी और उनके लिए प्रीमियम की लागत भी कम होगी।

मंत्रिमंडल में पेश प्रस्ताव के मुताबिक निर्विक (निर्यात ऋण विकास योजना) योजना के तहत निर्यात क्रेडिट के लिए ब्याज की दर गिरकर डॉलर के लिहाज से 3.15 फीसदी और रुपये के लिहाज से 7.35 फीसदी रहने की संभावना है। अभी क्रेडिट पर ब्याज दरें विदेशी मुद्रा में तीन फीसदी से छह फीस और रुपये के लिहाज से करीब 10 फीसदी है।

एक सरकारी अधिकारी ने कहा, 'मंत्रिमंडल में निर्विक योजना पर अगले एक या दो हफ्ते में विचार किया जाएगा। इसके तहत निर्यातकों को क्रेडिट पर प्रतिस्पर्द्धी ब्याज दरें मुहैया की जाएंगी।'

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (फियो) के आंकड़ों के मुताबिक निर्यात क्रेडिट में विदेशी मुद्रा की हिस्सेदारी करीब 53 फीसदी और रुपये की 47 फीसदी है। अधिकारी ने कहा, 'अब कारोबारी सीधे विदेशी मुद्राओं में निर्यात क्रेडिट ले सकते हैं, इसलिए मंत्रालय कुल निर्यात क्रेडिट में विदेशी मुद्राओं की हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता है।'

संशोधित निर्यात क्रेडिट बीमा योजना (ईसीआईएस) में भारतीय निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम (ईसीजीसी) के माध्यम से बैंकों को निर्यात क्रेडिट पर ऊंची बीमा कवरेज देकर निर्यात दरों को कम करने का लक्ष्य है। यह ब्याज अधिकतम दो तिमाही या ऋण को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित होने तक कवर किया जाएगा। अगर 90 दिन तक ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है तो ऋण को (एनपीए) घोषित कर दिया जाता है। इस योजना निर्यातकों के लिए कार्यशील पूंजी ऋण पर निर्यात क्रेडिट बीमा कवर का भी विस्तार करेगी जिससे निर्यात क्रेडिट पर कम ब्याज दरों में मदद मिलेगी।

इसके अलावा 80 करोड़ रुपये तक के खातों पर प्रीमियम की वार्षिक दर 0.6 फीसदी तक लाई जाएगी जबकि 80 करोड़ रुपये से अधिक के खातों पर इसे घटाकर 0.72 फीसदी किया जाएगा।

ईसीजीसी के अधिकारियों का कहना है कि वे तब तक बैंक के दस्तावेज और रिकॉर्ड नहीं खंगालेंगे जब तक ऋण पर नुकसान 10 करोड़ रुपये न पहुंच जाए। पहले यह सीमा एक करोड़ रुपये थी। (शेष पृष्ठ 4 पर)

...निर्यात पर जोर

- **निर्यात में गिरावट रोकने की कवायद में जुटी सरकार**
- **कम ब्याज दर और प्रीमियम लागत की पेशकश**
- **मंत्रिमंडल अगले कुछ दिनों में कर सकता है विचार**
- **बैंकों को निर्यात क्रेडिट पर ऊंची बीमा कवरेज**

खबरों में रहे स्टॉक

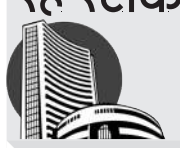

फोर्स मोटर्स

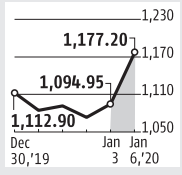

दिसंबर में वाहनों की बिक्री सालाना आधार पर 62 फीसदी बढ़ी

₹ 1,094.95 पिछला बंद भाव
₹ 1,177.20 आज का बंद भाव
▲ 7.51 %

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन

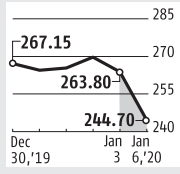

इराक पर पाबंदी लगाने की ट्रंप की धमकी, इराक के प्रतिरोध से कच्चा तेल चढ़ा

₹ 263.80 पिछला बंद भाव
₹ 244.70 आज का बंद भाव
▼ 7.24 %

बजाज फाइनैंस

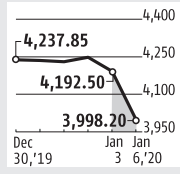

एसऐंडपी बीएसई सेंसेक्स में सबसे ज्यादा टूटने वाला शेयर

₹ 4,192.50 पिछला बंद भाव
₹ 3,998.20 आज का बंद भाव
▼ 4.63 %

अदाणी ग्रीन एनर्जी

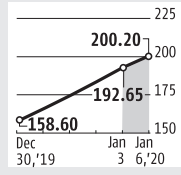

एफआईआई की हिस्सेदारी दिसंबर तिमाही में सर्वोच्च स्तर पर पहुंची

₹ 192.65 पिछला बंद भाव
₹ 200.20 आज का बंद भाव
▲ 3.92 %

रिलायंस इंडस्ट्रीज

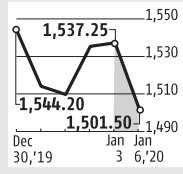

एक दिन में बाजार पूंजीकरण 24,000 करोड़ रुपये घटा

₹ 1,537.25 पिछला बंद भाव
₹ 1,501.50 आज का बंद भाव
▼ 2.33 %

संक्षेप में

आईपीओ के लिए एनएसई ने सेबी से संपर्क किया

देश के प्रमुख शेयर बाजार नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने सोमवार को कहा कि उसने अपने प्रारम्भिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिये पूंजी बाजार नियामक सेबी से संपर्क किया है और उम्मीद है कि इस साल सितंबर में आईपीओ बाजार में आ जाएगा। एनएसई के प्रबंध निदेशक और सीईओ विक्रम लिमये ने कहा, 'हमने आईपीओ की मंजूरी लेने के लिये सेबी से संपर्क किया है। इसके बाद हम मर्चेंट बैंकर नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। मर्चेंट बैंकर आईपीओ के लिए दस्तावेज का प्रारूप तैयार करने में मदद करेगा।' उन्होंने कहा कि एक्सचेंज इस कैलेंडर वर्ष की तीसरी तिमाही में आईपीओ ला सकता है। हालांकि, सेबी से इसकी मंजूरी मिलने के बाद ही यह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इस पेशकश में एक्सचेंज के मौजूदा शेयरधारक ही अपने शेयर बेचेंगे। *भाषा*

आईपीओ को तैयार ईएसएएफ फाइनैंस बैंक

ईएसएएफ स्मॉल फाइनैंस बैंक ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास 976 करोड़ रुपये जुटाने के लिये आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) दस्तावेज जमा कराए हैं। दस्तावेजों के अनुसार आईपीओ के तहत 800 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे और 176.2 करोड़ रुपये की बिक्री पेशकश लाई जाएगी। इसमें कहा गया है कि बैंक अपने बुक रनिंग लीड प्रबंधकों के साथ विचार विमर्श के बाद 300 करोड़ रुपये के आईपीओ पूर्व नियोजन पर विचार कर सकतर है। *भाषा*

आर-इन्फ्रा ने भुगतान में की चूक

कंपनी दिसंबर तिमाही में 1,048.70 करोड़ रुपये के भुगतान में विफल रही है

अमृता पिल्लई
मुंबई, 6 जनवरी

रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर ने दिसंबर 2019 की तिमाही में कुल 1,048.70 करोड़ रुपये के भुगतान में चूक की है। कंपनी ने सोमवार को एनएसई को भेजी जानकारी में ये बातें कही है।

इससे पहले जुलाई 2019 में कंपनी ने अपने लेनदारों के साथ इंटर-क्रेडिटर करार किया था, जिससे कंपनी को छह महीने की मोहलत मिल गई थी। आर-इन्फ्रा की सहायक रिलायंस नेवल ऐंड इंजीनियरिंग भी विगत में लेनदारों संग मूलधन व ब्याज भुगतान में चूक कर चुकी है।

सोमवार को एनएसई को भेजी सूचना में कंपनी ने कहा, इस तारीख तक कुल डिफॉल्ट 1,048.70 करोड़ रुपये रहा। खुलासे के मुताबिक, यह डिफॉल्ट बैंकों से कर्ज और कैश क्रेडिट जैसी सुविधा से जुड़ा हुआ है। कंपनी ने डिफॉल्ट की प्रकृति पर और जानकारी नहीं दी।

इंटर-क्रेडिटर करार पर और जानकारी के लिए आर-इन्फ्रा को भेजे गए ईमेल का जवाब नहीं मिला।

कर्ज व अन्य सुविधा पर कुल बकाया 4,597.06 करोड़ रुपये था। इसके अलावा कुल वित्तीय देनदारी (अल्पावधि व लंबी अवधि के कर्ज समेत) 6,073.66 करोड़ रुपये थी।

डिफॉल्ट संबंधी खुलासा ऐसे समय में हो रहा है जब आर-इन्फ्रा की योजना मौजूदा वर्ष में कर्जमुक्त बनने की है। पिछले महीने गोवा सरकार से मिले आर्बिट्रेशन अवार्ड पर एक बयान में कंपनी ने कहा था, इस रकम का इस्तेमाल लेनदारों को भुगतान करने और कंपनी का कर्ज घटाने में किया जाएगा। कंपनी का इरादा साल 2020 में कर्जमुक्त होने का है। कंपनी ने गोवा सरकार के खिलाफ 350 करोड़ रुपये का अर्बिट्रेशन अवार्ड जीता है, जिसमें ब्याज शामिल है। इससे पहले 23 दिसंबर को कंपनी ने कहा था कि उसे दामोदर वैली कॉरपोरेशन के खिलाफ 1,250 करोड़ रुपये का आर्बिट्रेशन अवार्ड जीता है।

समूह की कंपनियों में आरकॉम पहले से ही दिवालिया प्रक्रिया से जूझ रही है

जुलाई में रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर ने कहा था कि उसने लेनदारों के साथ इंटर-क्रेडिटर करार पर हस्ताक्षर किए हैं, जो छह महीने के भीतर समाधान योजना लागू करने के बारे में है। यह करार कंपनी के एकल कर्ज को लेकर था, जो मार्च 2019 में करीब 6,000 करोड़ रुपये था।

परिसंपत्ति मुद्रीकरण की योजना के तहत कंपनी ने मुंबई वितरण कारोबार अगस्त 2018 में 12,700 करोड़ रुपये में बेच दिया। मार्च में कंपनी दिल्ली-आगरा टोल रोड प्रोजेक्ट 3,600 करोड़ रुपये में बेचने पर सहमत हुई। पिछले साल जुलाई में कंपनी ने मुंबई की कार्यालय परिसंपत्ति लंबी अवधि के लिहाज से पट्टे पर देने की योजना की घोषणा की थी।

जून 2019 में समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी ने कहा था कि उसके समूह ने अप्रैल 2018 से मई 2019 के बीच लेनदारों को 35,000 करोड़ रुपये चुकाया है, जो मुख्य रूप से परिसंपत्ति बिक्री के जरिए चुकाए गए।

समूह कंपनियों में आरकॉम पहले ही दिवालिया प्रक्रिया का सामना कर रही है। मई 2019 में एनसीएलटी ने आरकॉम के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिय शुरू की।

आपसी मतभेद दूर करें टाटा और वाडिया: उच्चतम न्यायालय

एजेंसियां
नई दिल्ली, 6 जनवरी

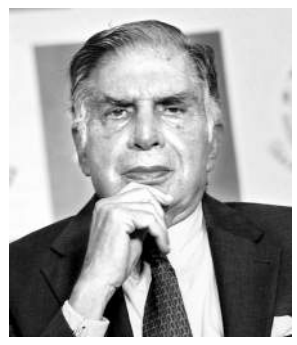

उच्चतम न्यायालय ने आज बॉम्बे डाइंग के चेयरमैन नुस्ली वाडिया और टाटा संस के मानद चेयरमैन रतन टाटा को मानहानि मामले में आपस में बैठकर मतभेद दूर करने को कहा। वाडिया को 2016 में टाटा समूह की कुछ कंपनियों के बोर्ड से बाहर कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने रतन टाटा और टाटा संस के कुछ निदेशकों के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था।

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अगुआई वाले पीठ ने कहा, 'आप दोनों परिपक्व लोग हैं। आप उद्योग जगत के अगुआ हैं। आप साथ बैठकर अपने मतभेदों को दूर क्यों नहीं करते। क्या आपको इस तरह का मुकदमा लड़ने की जरूरत है?'

पीठ इस मामले को निपटाना चाहता था। उसने बंबई उच्च न्यायालय के इस रुख को सही ठहराया कि इस मामले में मानहानि की मंशा नहीं थी। लेकिन वाडिया के वकील ने कहा कि वह मानहानि के एक अलग मामले में अपने मुवक्किल का सुझाव लेना चाहते हैं। इसके बाद मामले की सुनवाई 13 जनवरी तक टाल दी गई।

इससे पहले वाडिया के वकील नीरज किशन कौल ने कहा कि उनके मुवक्किल टाटा समूह के खिलाफ नहीं हैं और वह उनकी छवि को हुए नुकसान के एवज में कोई मुआवजा नहीं मांग रहे हैं। वह उन लोगों के खिलाफ हैं जिन्होंने उन पर मिथ्या आरोप लगाए। ऐसे लोगों को अपने आरोप वापस लेने चाहिए।

रतन टाटा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वाडिया ने एक वैधानिक नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि बंबई उच्च न्यायालय का कहना है कि इस मामले में किसी की छवि खराब करने की कोई मंशा नहीं थी और इसे देखते हुए अदालत को याचिका को निपटा देना चाहिए। जैसे ही पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले को सही ठहराते हुए आदेश सुनाना बंद किया कौल ने कहा कि उनके मुवक्किल इस मामले में मानहानि याचिका को आगे बढ़ाना चाहते हैं।

गोदरेज कंज्यूमर को बिक्री वृद्धि एक अंक में रहने का अनुमान

गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (जीसीपीएल) ने स्टॉक एक्सचेंजों को दी जानकारी में कहा कि उसकी बिक्री वृद्धि अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में स्थानीय बाजार में मध्यम एक अंक की तुलना में मजबूत रहने की संभावना है। जीसीपीएल ने कहा है कि भारत में कमजोर मांग के बावजूद कंपनी अपने व्यवसाय को तेजी से बढ़ाने में सफल रही है।

हाल के महीनों में आई चुनौतियों का जिक्र करते हुए जीसीपीएल ने कहा है, 'तिमाही के दौरान हमने परिचालन के अपने कुछ क्षेत्रों में मिश्रित मांग दर्ज की। सामान्य खपत में मंदी की वजह से भारत में मांग चुनौतीपूर्ण बनी रहेगी।'

हालांकि बिक्री वृद्धि में सुधार उसके घरेलू कीटनाशक व्यवसाय में तेजी और नई उत्पाद पेशकशों की मदद से देखने को मिला। मजबूत विपणन अभियानों और खास उपभोक्ता पेशकशों से भी बिक्री को मदद मिली। *बीएस*

कमजोर रह सकता है आईटी कंपनियों का राजस्व

देबाशिष महापात्र
बेंगलूरु, 6 जनवरी

बड़ी घरेलू सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेवा कंपनियों पर अपेक्षाकृत कमजोर समझी जाने वाली तीसरी तिमाही में दबाव दिखने की आशंका है। हालांकि कमजोर रुपये और अनुकूल उपायों की मदद से परिचालन मार्जिन में सुधार आने की संभावना है।

विश्लेषकों का कहना है कि प्रमुख पांच कंपनियों - टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, विप्रो और टेक महिंद्रा का डॉलर राजस्व 1.3 प्रतिशत से 3.5 प्रतिशत के दायरे में बढ़ने की संभावना है।

तीसरी तिमाही में टीसीएस के परिचालन मार्जिन में पूर्ववर्ती तिमाही के मुकाबले 90 आधार अंक का सुधार आने की संभावना है, जबकि इन्फोसिस द्वारा मार्जिन में तिमाही आधार पर 80 आधार अंक की तेजी दर्ज किए जाने का अनुमान है।

ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने एक रिपोर्ट में कहा है, 'मौसमी आधार पर तीसरी तिमाही को कमजोर समझा जाता है और साथ ही बैंकिंग तथा वित्तीय सेवा (बीएफएसआई) और रिटेल जैसे प्रमुख वर्टिकलों में कमजोरी से वृद्धि पर गतिरोध पैदा होगा। हमारा मानना है कि टियर-1 कंपनियां मौद्रिक संदर्भ में 0-2 प्रतिशत की धीमी वृद्धि दर्ज करेंगी।'

अक्टूबर-दिसंबर अवधि के लिए, बीएफएसआई और रिटेल वर्टिकलों में कम

ग्राहक खर्च की वजह से टीसीएस और इन्फोसिस, दोनों को कमजोर राजस्व वृद्धि दर्ज किए जाने की संभावना है। प्रमुख वर्टिकलों में नरमी के बावजूद, दोनों कंपनियों के लिए ऑर्डर प्रवाह की स्थिति मजबूत बनी हुई है।

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट में कहा गया है, 'टीसीएस में कुल अनुबंध वैल्यू (टीसीवी) को फीनिक्स ग्रुप के साथ हुए बड़े सौदे का लाभ मिलना चाहिए। इसी तरह, इन्फोसिस में शुद्ध नई टीसीवी को सर्विसेज आस्ट्रेलिया ऐंड टेलीनेट के साथ हुए सौदे (तीसरी तिमाही के दौरान) से फायदा मिलने का अनुमान है।' तीसरी सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजीज के राजस्व में तिमाही आधार पर 1.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज किए जाने की संभावना है। बौद्धिक संपदा परिसंपत्तियों की खरीदारी के लिए 1.8 अरब डॉलर का निवेश करने वाली एचसीएल वित्त वर्ष 2020 में अपने राजस्व अनुमान को बढ़ाकर 15-17 प्रतिशत कर चुकी है, जबकि शुरू में यह 14-16 प्रतिशत था। रुपये में गिरावट से भी कई कंपनियों को मार्जिन प्रोफाइल में मदद मिलने की संभावना है।

मझोले आकार की कंपनियों में एलऐंडटी इन्फोटेक द्वारा तिमाही आधार पर 4.5 प्रतिशत की राजस्व वृद्धि दर्ज किए जाने का अनुमान है।

एनबीएफसी ऋण वृद्धि बेहतर रहने के आसार

टाटा कैपिटल के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्याधिकारी राजीव सभरवाल ने कहा कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) क्षेत्र वित्त वर्ष 2021 में बेहतर ऋण वृद्धि दर्ज करेगा, लेकिन उसे अपना बहीखाता 20 प्रतिशत से ज्यादा की दर से बढ़ाने में कुछ समय लगेगा। सभरवाल ने कहा, 'इस सेक्टर में वृद्धि स्पष्ट रूप से अर्थव्यवस्था में बदलाव से संबंधित है। यदि अर्थव्यवस्था में मंदी आती है तो आप एनबीएफसी क्षेत्र में भी इसका समान असर देखेंगे। मेरा मानना है कि एनबीएफसी में इस साल वृद्धि की रफ्तार पिछले साल की तुलना में नरम रहेगी। जहां तक अगले साल की बात है तो हमें उम्मीद है कि ऋण वितरण में सुधार आएगा। इस साल, ऋण वितरण पिछले साल के मुकाबले कमजोर है।'

उन्होंने कहा, 'अगले साल, हम ऋण वितरण में सुधार देखेंगे, लेकिन बहीखाते में 20 प्रतिशत की वृद्धि में एक साल और लगेगा।' *बीएस*

तेल की कीमतों ने बढ़ाई कंपनियों की चिंता

तेल विपणन, विमानन, टायर और सीमेंट कंपनियां लागत में बढ़ोतरी का पूरा भार ग्राहकों पर नहीं डाल पाएंगी, लेकिन पेंट और एडहेसिव कंपनियां बेहतर स्थिति में रहेंगी

श्रीपद ए ऑटे और राम साहू
मुंबई, 6 जनवरी

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और उसके ब्रेंट क्रूड तेल के दामों पर भी असर से भारतीय कंपनियों की चिंताएं बढ़ गई हैं। ब्रेंट क्रूड तेल की कीमतें सोमवार को करीब 70 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गईं। देश में कंपनियां पहले ही कमजोर आर्थिक स्थिति से जूझ रही हैं। अब उन्हें लागत में बढ़ोतरी और उसकी वजह से मार्जिन घटने का संकट भी नजर आ रहा है।

बाजार में भी यह चिंता साफ नजर आई। कच्चे तेल की कीमतों से तुलनात्मक रूप से अधिक जुड़ाव रखने वाले क्षेत्रों जैसे तेल विपणन (ओएमसी), विमानन, पेंट एवं एडहेसिव, सीमेंट और टायर के शेयरों की कीमतों में सात फीसदी तक की गिरावट दर्ज की गई, जबकि एसऐंडपी बीएसई सेंसेक्स करीब दो फीसदी लुढ़ककर बंद हुआ।

इस समय मांग कमजोर बनी हुई है। ऐसे में कंपनियां का कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का बोझ ग्राहकों पर डालने में सक्षम होना अहम होगा। इसकी वजह यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी की अनदेखी नहीं की जा सकती। हालांकि बहुत से विशेषज्ञों का मानना है कि हालात सामान्य होने पर तेल की कीमतें नीचे आ जाएंगी।

इंडिया रेटिंग्स में मुख्य अर्थशास्त्री देवेंद्र पंत ने कहा, 'अमेरिका और ईरान के बीच यह तनाव कितने लंबे समय तक बना रहेगा, इसे लेकर कुछ कहना मुश्किल है। हालांकि इससे कच्चे तेल की आपूर्ति में अवरोध पैदा होगा और अगर तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची बनी रहीं तो यह बड़ी चिंता की बात होगी।' कुछ अन्य विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर हालात बदतर हुए तो ब्रेंट क्रूड तेल के दाम 70 डॉलर प्रति बैरल या वित्त वर्ष 2019 की औसत कीमतों से 8-9 फीसदी अधिक रहेंगे।

ऐसे माहौल में इंडियन ऑयल कॉरपोरेश जैसी तेल विपणन कंपनियों पर बड़ा असर पड़ सकता है क्योंकि इसका उनका रिफाइनिंग और मार्केटिंग मार्जिन सीधे प्रभावित होगा। हालांकि तेल विपणन कंपनियों ने हाल में ऊंची कीमतों का बोझ ग्राहकों पर डालने की अपनी क्षमता दिखाई है। मोतीलाल ओसवाल फाइनैंशियल सर्विसेज के विश्लेषक स्वर्णेंदू भूषण का मानना है कि तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी से तेल विपणन कंपनियों के लिए बढ़ी कीमतों का बोझ ग्राहकों पर डालना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अगर वे ऐसा नहीं कर पाईं तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (बीपीसीएल) के विनिवेश को लेकर सवाल खड़ा हो जाएगा। तेल विपणन कंपनियों पर अतिरिक्त दबाव अधिक ब्याज लागत के रूप में आएगा क्योंकि तेल की ऊंची कीमतों से उनकी कार्यशील पूंजी की जरूरत बढ़ने के आसार हैं।

हालांकि निर्मल बांग के अनुसंधान प्रमुख सुनील जैन की राय अलग है। उनका मानना है कि तेल विपणन कंपनियां लागत के बोझ को ग्राहकों पर डालने के लिए ईंधन की कीमतें बढ़ा सकती हैं। वहीं बीपीसीएल के विनिवेश की योजना को मद्देनजर रखते हुए ईंधन की कीमतों को नियंत्रित करने में सरकार के दखल देने के आसार नहीं हैं। हालांकि इसका पता आने वाले समय में ही चल पाएगा।

जैन ने कहा कि हालांकि विमानन कंपनियों के लिए कीमतों में बढ़ोतरी मुश्किल साबित हो सकती है क्योंकि इससे यात्रियों की संख्या प्रभावित हो सकती है। विमानन कंपनियों की परिचालन लागत में करीब 40 फीसदी हिस्सा कच्चे तेल का है।

अन्य क्षेत्र जिन पर कच्चे तेल की ऊंची कीमतों का नकारात्मक असर पड़ेगा, उनमें टायर और सीमेंट शामिल हैं। ये दोनों क्षेत्र इस समय कमजोर मांग के दौर से गुजर रहे हैं। पेंट और एडहेसिव पर भी तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर पड़ेगा। लेकिन ये क्षेत्र कीमत बढ़ाने की स्थिति में हैं, इसलिए उनके लिए मार्जिन को बनाए रखना बड़ी चिंता नहीं होगी।

कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का फायदा केवल तेल एवं गैस उत्पादक क्षेत्र को मिलेगा क्योंकि इसे अपने उत्पादों के ज्यादा दाम मिलेंगे। हालांकि पीएसयू के विनिवेश से संबंधित मुद्दों के कारण सोमवार को ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के शेयर करीब 1-2 फीसदी नीचे थे। साफ तौर पर दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में यह देखना रोचक होगा कि भारतीय कंपनियां मार्जिन और मात्रात्मक वृद्धि के लिहाज से कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से कैसे निपटती हैं।

तेल की चिंता से लुढ़के शेयर

	कीमत	1-दिन का बदलाव
विमानन		
इंटरग्लोब एविएशन	1,327	-2.5
स्पाइसजेट	105	-1.1
वाहन		
अशोक लीलैंड	80	-3.9
मारुति सुजूकी	7,040	-3.0
टाटा मोटर्स	186	-2.9
हीरो मोटोकॉर्प	2,369	-2.7
तेल कंपनियां		
ओएनजीसी	126	-1.8
ऑयल इंडिया	154	-1.4
पेंट		
कनसाई नेरोलैक	494	-4.1
बर्जर पेंट्स	490	-3.8
एशियन पेंट्स	1,708	-2.5
तेल रिफाइनिंग एवं पेट्रोकेमिकल		
एचपीसीएल	245	-7.2
बीपीसीएल	469	-2.7
रिलायंस इंड.	1,502	-2.3
आईओसीएल	125	-1.5

आंकड़े: 6 जनवरी 2020 तक के हैं
सूची में बीएसई-500 कंपनियां शामिल हैं
स्रोतः एक्सचेंज बीएस रिसर्च ब्यूरो द्वारा

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 72 के पार

अनूप रॉय
मुंबई, 6 जनवरी

शेयर बाजार से संकेत लेते हुए सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपया कारोबारी सत्र में 72 के पार निकल गया। इसके अलावा ईरान-अमेरिका के बीच तनाव के कारण कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का भी इस पर असर रहा। कारोबार के अंत में स्थानीय मुद्रा में सुधार दर्ज हुआ क्योंकि निर्यातकों ने डॉलर की बिकवाली की। करेंसी डीलरों ने कहा, भारतीय रिजर्व बैंक ने बाजार में हस्तक्षेप नहीं किया।

डॉलर के मुकाबले रुपया 71.94 पर बंद हुआ, जो एक दिन पहले 71.80 पर बंद हुआ था। इसकी वजह कच्चे तेल की कीमत 70 डॉलर के पार निकलना रही। शुक्रवार को इरान के जनरल की मौत के बाद डॉलर के मुकाबले रुपया 0.61 फीसदी घटा था।

मुद्रा बाजार का मानना है कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव पूर्ण युद्ध में शायद तब्दील नहीं होगा, लेकिन कुछ समय तक तनाव रहेगा। इसके अलावा चीन के साथ कारोबारी तनाव के कारण यह साल रुपये के लिए बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है।

क्वांटआर्ट मार्केट्स सॉल्युशंस के प्रबंध निदेशक समीर लोढ़ा ने कहा, व्यापार युद्ध के अतिरिक्त किसी और तरह का युद्ध वैश्विक बाजारों और जोखिम के लिहाज से खराब होगा। उभरते बाजारों की मुद्राओं के मुकाबले रुपये पर अपेक्षाकृत ज्यादा असर होगा क्योंकि भारत तेल के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है और भारत का ईरान के साथ अच्छे कारोबारी संबंध हैं। उन्होंने कहा, निवेशक सुरक्षित मुद्राओं मसलन जापानी येन की ओर जा र हे हैं और 10 साल के यूएस बॉन्ड में निवेश कर रहे हैं।

डॉलर इंडेक्स 0.22 फीसदी टूटकर 96.63 पर रहा। एक विदेशी बैंक के कहा, अगर युद्ध नहीं होता है तो रुपये के लिए 72.50 प्रति डॉलर अच्छा प्रतिरोध स्तर होगा। उन्होंने कहा, अगर युद्ध के हालात बनते हैं और कच्चा तेल प्रभावित होता है तो कोई नहीं कह सकता कि रुपया कहां जाएगा।

करेंसी डीलर अब अपने समीकरण में कच्चे तेल की कीमत को ध्यान में रख रहे हैं। आम बजट में कच्चे तेल कीमत 65 डॉलर प्रति बैरल रहने का अनुमान जताया गया है। अगर यह उससे ऊपर जाता है तो भारत का राजकोषीय घाटा बढ़ जाएगा।

मैकलाई फाइनैंशियल के उपाध्यक्ष रितेश भंसाली ने कहा, अगर कच्चा तेल 70 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर टिकता है तो रुपये पर भारी दबाव होगा। यह इस पर निर्भर करता है कि तेल कैसी प्रतिक्रिया जताता है।

विश्लेषकों को लग रहा है कि भूराजनैतिक संकट कुछ दिनों तक बना रहेगा, जिसे तेल की कीमतें प्रभावित रहेंगी और रुपया समेत उभरते बाजारों की मुद्राएं इसकी जद में आ जाएंगी। एमके ग्लोबल फाइनैंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख राहुल गुप्ता ने कहा, हमें लगता है कि हाजिर भाव 72.25 से 72.50 रुपये तक होगा और यह 71.50 तक नीचे आएगा। जैसे-जैसे हम माह के आखिर की ओर बढ़ेंगे, हम एसबीआई कार्ड के आईपीओ में डॉलर का प्रवाह देख सकते हैं।

इराक पर धमकी से तेल पर चिंता

ईरान से भारत का आयात 2018-19 के 2.39 करोड़ टन से घटकर मौजूदा वित्त वर्ष में 17 लाख टन रह गया

शाइन जैकब
नई दिल्ली, 6 जनवरी

अमेरिका द्वारा इराक पर प्रतिबंध लगाने की धमकी के बाद सोमवार को कच्चे तेल की कीमतें 70 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गईं। इससे वैश्विक बाजार में आपूर्ति पर दबाव बढ़ सकता है। सप्ताहांत की तुलना में वैश्विक कीमतों में वृद्धि से वाहन ईंधन की खुदरा कीमतों पर प्रभाव पड़ा है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत रविवार के 75.54 रुपये की तुलना में सोमवार को 75.69 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गई, जो 13 महीने का सर्वाधिक ऊंचा स्तर है। इसी तरह डीजल कीमत रविवार के 68.51 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 68.68 रुपये पर पहुंच गई।

ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद, इराकी संसद ने अमेरिका सैनिकों को तुरंत देश छोड़ने को कहा था। इस निर्णय से अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप प्रशासन ने नाराजगी जताई है और इराक पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है।

ईरान से भारत का आयात 2018-19 के 2.39 करोड़ टन से घटकर मौजूदा वित्त वर्ष में 17 लाख टन रह गया है। रेटिंग एजेंसी इक्रा की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि इराक में सैन्य टकराव बढ़ने से वहां प्रतिदिन 46 लाख बैरल कच्चे तेल का उत्पादन खतरे में पड़ सकता है जिसका भारत को होने वाली कच्चे तेल की आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है और वैश्विक रूप से तेल कीमतों में तेजी आ सकती है। इसके अलावा, यदि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल टैंकर गतिविधियों को रोकता है तो इससे कीमतें और चढ़ सकती हैं।

बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) में पार्टनर एवं निदेशक अनिर्बन मुखर्जी ने कहा, 'तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था के तौर पर हम कच्चे तेल आयात पर निर्भर बने रहेंगे। कीमतों में अस्थिरता का आकलन नहीं किया जा सकता और हमारा आयात मजबूत बना रहेगा। मुख्य ध्यान इस पर रहना चाहिए कि इस घटनाक्रम के खिलाफ हमें स्वयं को किन उपायों के जरिये जोखिम से दूर बनाए रखना है। हमें अच्छी श्रेणी के कच्चे तेल की खरीदारी, रणनीतिक तौर पर भंडारण और मांग प्रबंधन पर ध्यान देने की जरूरत है।'

इक्रा की रिपोर्ट में कहा गया है कि कच्चे तेल को अमेरिकी इन्वेंट्री में आई भारी गिरावट से भी मदद मिली है। हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी के प्रबंध निदेशक पी इलांगो ने कहा, 'शेल की आवक ने पिछले तीन वर्षों में कच्चे तेल की कीमतों में संतुलन बनाए रखने का कार्य किया था। इस वजह से भू-राजनीतिक कारकों का असर घटा था। हालांकि यदि इराक पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो इससे निश्चित तौर पर आपूर्ति कुछ हद तक प्रभावित होगी।'

इक्रा ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नकारात्मक है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमत में प्रत्येक 1 डॉलर प्रति बैरल की वृद्धि से देश का आयात बिल 1.4 अरब डॉलर तक बढ़ेगा। दूसरी तरफ, कच्चे तेल में प्रत्येक 10 डॉलर प्रति बैरल की वृद्धि से राजकोषीय घाटा जीडीपी के लगभग 0.1 प्रतिशत तक बढ़ेगा।

कच्चे तेल का आयात

वर्ष	आयात (करोड़ टन)	वैल्यू (अरब डॉलर)
2018-19	15.1	78.6
2019-20	14.99	69.5

स्रोतः पीपीएसी
आंकड़े अप्रैल से नवंबर के बीच के हैं

सीसीबी की समयसीमा नहीं बढ़ाएगा आरबीआई

पृष्ठ-1 का शेष

आरबीआई ने रिपोर्ट में कहा कि केंद्रीय बैंक सरकारी बैंकों में पूंजी तो डाल रही है, लेकिन यह सीसीबी सहित न्यूनतम नियामकीय शर्तें पूरी करने भर ही पर्याप्त है। रिपोर्ट में कहा गया है,' सीसीबी के अंतिम किस्त का क्रियान्वयन 31 मार्च 2020 तक टलने से इन बैंकों को थोड़ी राहत मिल गई। अर्थव्यवस्था की वित्तीय जरूरत के अनुरूप ऋण आवंटन की उनकी क्षमता के लिए उनके पास न्यूनतम नियामकीय शर्तों से अधिक पूंजी होनी चाहिए। इससे इन बैंकों को जोखिम लेने और इससे निपटने का साहस आएगा।'

2.5 प्रतिशत सीसीबी में सामान्य इक्विटी टायर-1 कैपिटल है, जो 9 प्रतिशत के न्यूनम पूंजी पर्याप्त नियम से अधिक है। इस अहम बात पर भी नजरें होंगी कि वित्त वर्ष 2020 में सरकारी बैंक कितना लाभांश देते हैं। बेसल-3 पूंजी दिशानिर्देश से संबंधित आरबीआई के जुलाई 2015 के परिपत्र में कहा गया है, 'सुरक्षित पूंजी में ह्रास की स्थिति में बैंकों को अपने कुछ वैकल्पिक खर्चों में कमी कर इसमें मजबूती लानी चाहिए। इनमें लाभांश भुगतान, शेयर पुनर्खरीद और कर्मचारियों के बोनस में कमी आदि शामिल हैं।'पूर्व गवर्नर ऊर्जित पटेल की अध्यक्षता में आरबीआई के निदेशक मंडल की बैठक में सीसीबी की समस सीमा टलना कुछ प्रमुख निर्णयों में शामिल था।

ईरान ने ट्रंप का सिर कलम करने पर रखा 8 करोड़ डॉलर का इनाम

एजेंसियां
तेहरान/वॉशिंगटन, 6 जनवरी

ईरान के रिवॉल्यूनरी गार्ड्स के कमांडर कासिम सुलेमानी के जनाजे में लाखों लोग शामिल हुए। विभिन्न रिपोर्टों के मुताबिक एक खौफनाक लाइव प्रसारण में ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप को मारने वाले को 8 करोड़ डॉलर का इनाम देने का ऐलान किया है और व्हाइट हाउस पर हमले का प्रण लिया है।

कमांडर की बेटी जेनब सुलेमानी ने मातम मनाने वालों से कहा, 'अमेरिका और यहूदीवाद को यह समझ लेना चाहिए कि मेरा पिता का बलिदान बदले के मोर्चे पर जागृति लाएगा और उनके लिए एक काला दिन लेकर आएगा और उनके घरों को जमींदोज कर देगा।' जेनब ने टेलीविजन पर अपने संबोधन में कहा, 'ट्रंप यह मत सोचो कि मेरे पिता के बलिदान के बाद सब कुछ खत्म हो गया है।'

सुलेमानी के जनाजे में उमड़ी भीड़ 1989 में इस्लामिक रिपब्लिक के संस्थापक अयातुल्लाह रुहोल्लाह खुमैनी के जनाजे में उमड़ी भीड़ के बाद सबसे अधिक थी। अयातुल्लाह रुहोल्लाह खुमैनी उस क्रांति के नेता थे, जिन्होंने ईरान को अमेरिका के साथ राजनीतिक टकराव की राह पर खड़ा किया। ईरान के मौजूदा सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खुमैनी जनाजे में रो पड़े। ईरानी कमांडरों ने अमेरिकी हमले के बाद कई धमकियां दी हैं। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की हवाई सेना के प्रमुख अमीराली हाजीजादेह ने कहा, 'ट्रंप को मारने से भी बदला पूरा नहीं होगा। शहीद सुलेमानी के खून का बदला तभी पूरा होगा जब अमेरिका को क्षेत्र से पूरी तरह बाहर निकाल दिया जाएगा।'

संक्षेप में

आर्थिक मुद्दों पर केंद्र को बदनाम कर रहीं कुछ ताकतें

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि आर्थिक स्थिति को लेकर कई ताकतें केंद्र को 'बदनाम' करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सरकार व्यापारियों के समक्ष आ रही समस्याओं को समझती है और उनके समाधान की दिशा में काम कर रही है। कॉनफेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय महाधिवेशन में रक्षा मंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुस्ती वैश्विक आर्थिक मंदी का हिस्सा है। भारत की तुलना में विकसित देश इससे अधिक प्रभावित हुए हैं। सिंह ने कहा, 'देश में कई ऐसी ताकतें हैं जो आर्थिक मुद्दों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन सरकार को न केवल व्यापारियों के मुद्दों की जानकारी है बल्कि वह उनके समाधान के लिए भी काम कर रही है।' *भाषा*

कानूनी, वित्त विशेषज्ञों की नियुक्ति करेगी एनएफआरए

वित्तीय मामलों की रिपोर्टिंग पर नजर रखने के लिये बनाई गई 'दि नेशनल फाइनैंसियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (एनएफआरए)' अपने कार्यबल को मजबूत बनाने के लिए वित्त और कानूनी क्षेत्र के सलाहकारों की नियुक्ति करेगी। लेखा परीक्षा यानी आडिट कार्यों की निगरानी के लिये बनाई गई इस स्वतंत्र संस्था ने सलाहकार और वरिष्ठ सलाहकार के दस पदों के लिये आवेदन मंगाए हैं। नियुक्ति एक साल के अनुबंध आधार पर होगी। *भाषा*

दूरसंचार उद्योग ने सरकार से मांगा सस्ता कर्ज

मेघा मनचंदा
नई दिल्ली, 6 जनवरी

दूरसंचार उद्योग ने आज पूंजी की लागत घटाने में मदद के लिए कम ब्याज दरों और आसान वित्तपोषण की मांग की है। उद्योग के प्रतिनिधियों ने दूरसंचार मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की, जिससे वे कर्ज से लदे इस क्षेत्र की मदद के लिए अपने सुझावों से सरकार को अवगत करा सकें। दूरसंचार विभाग इन सुझावों को वित्त मंत्रालय के पास विचार के लिए भेजेगा।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि ज्यादातर मांगें पहले की ही तरह थीं, जिसमें शुल्क घटाना शामिल है। अधिकारी ने कहा कि एक सुझाव इनपुट लाइन क्रेडिट से जुड़ा हुआ है। उद्योग ने टेलीकॉम कंपनियों को कम ब्याज दरों पर मुहैया कराए जाने, लाइसेंस शुल्क, स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) पर जीएसटी खत्म किए जाने और संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफंड की भी मांग की है।

इसके अलावा उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि टेलीकॉम टॉवरों को इनपुट टैक्स क्रेडिट के मामले में संयंत्र व मशीनरी की परिभाषा में डाला जाना चाहिए और मेक इन इंडिया को आगे और प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित कोष का गठन किया जाना चाहिए, जिसका इस्तेमाल दूरसंचार संयंत्रों की खरीद में हो सके।

बैठक में मौजूद एक प्रतिनिधि ने कहा कि उद्योग ने दूरसंचार मंत्रालय, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) और उद्योग के हिस्सेदारों को मिलाकर एक कार्यसमूह के गठन का भी अनुरोध किया है, जो इनपुट लाइन क्रेडिट के सिद्धांतों को स्वीकार करने के लिए दिशानिर्देश बनाने का काम करेगा।

उन्होंने कहा कि दूरसंचार उद्योग पूंजी पर आधारित है और इसके लिए सस्ती दरों पर घरेलू स्रोतों से धन जुटाने की जरूरत है। एक और प्रतिनिधि ने कहा, 'हमने सरकार से अनुरोध किया है कि वह कम ब्याज दर पर धन मुहैया कराए, जिससे नेटवर्क के उन्नयन, रखरखाव व विस्तार का काम किया जा सके।'

अन्य सिफारिशों में यूएसओएफ अंशदान कम करके 3 प्रतिशत किया जाना, लाइसेंस शुल्क एजीआर का 1 प्रतिशत किया जाना शामिल है। उद्योग ने यह भी मांग की है कि नियामकीय शुल्क का भुगतान जीएसटी के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए।

संकट में फंसा दूरसंचार

एटीएस गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेसवे पर बना रही 5 आवासीय परियोजनाएं

3 प्रतिशत किया जाए यूएसओएफ अंशदान

1 प्रतिशत हो लाइसेंस शुल्क एजीआर का

- लाइसेंस शुल्क, स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क पर जीएसटी खत्म किए जाने व इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफंड की मांग
- इनपुट टैक्स क्रेडिट के मामले में टेलीकॉम टॉवरों को संयंत्र व मशीनरी की परिभाषा में डाला जाए

बीएसएनएल की युवा टीम देगी 4जी सेवा

मेघा मनचंदा
नई दिल्ली, 6 जनवरी

भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के एक महीने पूरे होने के बाद नए कैलेंडर वर्ष में कम कर्मचारियों वाली युवा टीम 4जी सेवाएं देने की प्रक्रिया शुरू करने वाली है। तकरीबन 78,300 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पैकेज का विकल्प चुना है, जो कंपनी के कुल कर्मचारियों पर होने वाले 14,500 करोड़ रुपये व्यय का आधा पाते हैं। सेवानिवृत्ति पैकेज से कर्ज के बोझ से दबी कंपनी के हर साल 9,000 करोड़ रुपये बचेंगे। कंपनी को अभी एक महीने का कर्मचारियों का वेतन देना है।

स्वतंत्र टेलीकॉम विशेषज्ञ महेश उप्पल ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि ज्यादा अंतर आएगा। हां, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पैकेज एक अहम कदम है और इससे ज्यादा कर्मचारी होने की शुरुआती चुनौतियों से निपटा जा सकता है। लेकिन बीएसएनएल की सेहत को लेकर संदेह इससे दूर नहीं होने जा रहा है। बीएसएनएल में इससे सुधार नहीं होगा क्योंकि इससे समस्या को लेकर कोई बदलाव नहीं हुआ है। बीएसएनएल की तकनीक, प्रतिस्पर्धात्मकता और प्रबंधन का मसला बना हुआ है।'

4 नवंबर 2019 को लागू बीएसएनएल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना 2019 के मुताबिक बीएसएनएल के सभी नियमित और स्थाई कर्मचारियों, जिसमें अन्य संस्थानों में या बीएसएनएल के बाहर डेपुटेशन पर काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं, और उनकी उम्र 50 साल या उससे ऊपर हो चुकी है, वे इस योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प चुन सकते हैं।

इसमें पात्र पाए जाने वाले कर्मचारियों को देय राशि में पूरे किए हुए हर साल के 35 दिन के बराबर वेजन और शेष बचे साल के 25 दिन के बराबर वेतन शामिल है। केंद्र सरकार ने 25 अक्टूबर 2019 को बीएलएनएल और महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड (एमटीएनएल) के लिए 69,000 करोड़ रुपये के पुनरुद्धार पैकेज की घोषणा की थी, जिसमें घाटे में चल रही दोनों कंपनियों का विलय, उनकी संपत्ति बेचकर धन जुटाना और कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प देना शामिल है, जिससे संयुक्त इकाई 2 साल में लाभ में आ सके।

बीएसएनएल के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक पीके पुरवार ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि 2 साल के भीतर बीएलएनएल एबिटा (अर्निंग बिफोर इंट्रेस्ट टैक्सेसन डेप्रिसिएशन ऐंड अमोर्टाइजेशन) पॉजिटिव होगी और 5 साल बाद कंपनी पीएटी (प्रॉफिट आफ्टर टैक्स) पॉजिटिव होगी।

BSNL Connecting India

युवा हुआ बीएसएनएल

कंपनी के 12 करोड़ ग्राहक हैं। कंपनी ने कुछ बैंक कर्ज के अग्रिम भुगतान के लिए बॉन्ड जारी कर धन जुटाने की योजना बनाई है। इश्यू बीएसएनएल द्वारा लाया जाएगा और इसे वित्त मंत्रालय से सॉवरिन गारंटी की जरूरत होगी। कंपनी इस वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में 4जी सेवा शुरू कर सकती है, जिसके लिए 12,000 करोड़ रुपये जुटाने होंगे और इसमें आंशिक रूप से बॉन्ड के माध्यम से धन जुटाया जाएगा।

डिफेंस एक्सपो में आएंगे 70 देश

बीएस संवाददाता
लखनऊ, 6 जनवरी

उत्तर प्रदेश में इस बार आयोजित हो रहे रक्षा मेले (डिफेंस एक्सपो) में 165 विदेशी कंपनियां हिस्सा लेंगी। प्रदेश में पहली बार आयोजित हो रहे डिफेंस एक्सपो में 70 देशों की रक्षा उत्पाद बनाने वाली कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। प्रदेश की योगी सरकार को डिफेंस एक्सपो के जरिए यहां प्रस्तावित डिफेंस कॉरिडोर में निवेश के बड़े प्रस्ताव मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने उम्मीद जताई है कि डिफेंस एक्सपो के आयोजन से बुंदेलखंड में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर के लिए 25000 करोड़ रुपये तक के निवेश प्रस्ताव मिल सकते हैं।

राजधानी लखनऊ में 5 फरवरी से शुरू हो रहे डिफेंस एक्सपो में इस बार 925 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं जो देश में अब तक आयोजित किसी भी एक्सपो से कहीं ज्यादा है। इससे पहले चेन्नई में बीते साल हुए डिफेंस एक्सपो में 702 कंपनियों ने हिस्सा लिया था। लखनऊ में हो रहा डिफेंस एक्सपो आकार में भी अब तक का सबसे बड़ा शो होने जा रहा है। बीते साल जहां चेन्नई में 80 एकड़ में इसका आयोजन हुआ था वही इस बार इसे 200 एकड़ जमीन पर आयोजित किया जा रहा है।

लखनऊ में एक्सपो

डिफेंस एक्सपो की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा प्रदेश के लिए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डीआईसी) की घोषणा के साथ ही राज्य सरकार ने अपनी डिफेंस ऐंड एयरोस्पेस मैनुफैक्चरिंग ऐंड इम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी घोषित की है। इसके तहत निवेशकों को निवेश के लिए आकर्षित किया जा रहा है। डीआईसी के तहत प्रदेश में अलीगढ़, झांसी, कानपुर, आगरा और चित्रकूट सहित लखनऊ में 6 मुख्य नोड्स चिह्नित किए गए हैं। इन जिलों में इकाइयों की स्थापना के लिए लैंड बैंक तैयार किया जा रहा है। बुंदेलखंड क्षेत्र में इन इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का भी निर्माण किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डीआईसी की सफलता के लिए डिफेंस एक्सपो 2020 अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस रक्षा मेले के जरिए डीआईसी में लगभग 25 हजार करोड़ रुपये का निवेश संभावित है। देश एवं विदेश के निवेशकों ने डीआईसी में निवेश के प्रति रुचि दिखाई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार द्वारा अपनी नई खरीद नीति शीघ्र ही घोषित की जाएगी, जिससे डीआईसी में निवेश को बल मिलेगा। प्रदेश में बन रहे रक्षा गलियारे के लिए स्थानीय छोटे व मझोले उद्यमियों के खास तौर पर प्रोत्साहन व सुविधाएं दी जा रही हैं।

डिफेंस एक्सपो की तैयारियों की समीक्षा के लिए रविवार को मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की।

सेवा गतिविधियां 5 महीने के उच्च स्तर पर

शुभायन चक्रवर्ती
नई दिल्ली, 6 जनवरी

सेवा क्षेत्र में दिसंबर महीने में मजबूत वृद्धि दर वापस आ गई। इस क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय कारोबार से मदद मिली है और यह 5 माह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। आज जारी वैश्विक सर्वे से यह जानकारी मिली है।

निक्केई इंडिया सर्विसेज पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) दिसंबर में 53.3 रहा, जो नवंबर के 52.7 से ज्यादा है। पीएमआई 50 अंक से ज्यादा रहना विस्तार व इससे कम रहना संकुचन के संकेत देता है।

अगस्त महीने में सेवा की वृद्धि 43 महीने के उच्च स्तर 54.7 पर थी और इसके बाद लगातार दो महीने इसमें संकुचन रहा। पिछले सप्ताह जारी इसी सर्वे के मुताबिक यह विनिर्माण गतिविधियों की तर्ज पर ही है, जो नवंबर के 51.2 की तुलना में दिसंबर में बढ़कर 52.7 हो गया है। यह अक्टूबर में दो साल के निचले स्तर पर था।

कुल बिक्री लगातार तीसरे महीने बढ़ी है और अक्टूबर 2016 के बाद या 3 साल से ज्यादा समय बाद सबसे तेज बढ़ोतरी हुई है। उन फर्मों ने ज्यादा वृद्धि दर्ज की है, जिन्होंने कारोबारी सुधार के फैसले प्रबंधन के स्तर पर लिए हैं और नई सेवाओं की पेशकश के साथ मांग के मुताबिक काम किया है।

नए बिजनेस ऑर्डर से समर्थन मिला, जो ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय बाजार से आया। सर्वे से पता चलता है कि सेवाओं के निर्यात में लगातार 10वें महीने बढ़ोतरी हुई है। कुछ सुधार के बावजूद सितंबर के बाद सबसे तेज बढ़ोतरी हुई है।

सर्वे में कहा गया है कि इसके परिणामस्वरूप नौकरियों का सृजन भी 3 महीने के उच्च स्तर पर रहा। 28 महीनों की सामान्य गति के बाद रोजगार अगस्त के बाद से सबसे तेज बढ़ा है।

बहरहाल कारोबार का बकाया बढ़ना जारी है, हालांकि रफ्तार सुस्त है। क्लाइंट के लंबित भुगतान और लगातार तीसरे महीने काम में तेजी आने से बकाया बढ़ रहा है।

इसके साथ ही बढ़ोतरी की औसत दर के साथ औसत इनपुट लागत बढ़ी है। इसमें 7 साल में सबसे तेजी देखी गई है। 2019 में इनपुट महंगाई दर बढ़ी है। इसके पहले महीने में महंगाई दर 13 महीने के उच्च स्तर पर थी। सर्वे में जवाब देने वाले ज्यादातर लोगों ने कहा कि खाद्य, ईंधन, परिवहन और मेडिकल उत्पादों का बोझ बढ़ने से ऐसा हुआ है।

आईएचएस मार्किट की प्रधान अर्थशास्त्री पॉलियाना डी लीमा ने कहा, 'बहरहाल सर्वे के परिणाम में चिंता की बात मूल्य सूचकांकों से मिलती है। जहां 2019 के शुरुआत में महंगाई कम थी, इस तिमाही में लगातार इनपुट लागत की महंगाई बढ़ी है। सेवा फर्मों के व्यय में दिसंबर में 7 साल में सबसे तेज बढ़ोतरी देखी गई है।'

बहरहाल सेवाओं के प्रावधान के लिए औसत मूल्य मामूली बढ़ा है। आंकड़ों से पता चलता है कि इनपुट लागत की दरों व आउटपुट शुल्क की महंगाई में अंतर पहले के वर्षों की तुलना में बहुत कम है।

इनपुट लागत बढ़ने को लेकर सर्वे में जताई गई चिंता

- निक्केई इंडिया सर्विसेज पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स दिसंबर में 53.3 रहा, जो नवंबर के 52.7 से ज्यादा
- कुल बिक्री लगातार तीसरे महीने बढ़ी है और अक्टूबर 2016 के बाद या 3 साल से ज्यादा समय बाद सबसे तेज बढ़ोतरी हुई
- नए बिजनेस ऑर्डर से समर्थन मिला, जो ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय बाजार से आया नौकरियों का सृजन भी 3 महीने के उच्च स्तर पर

अक्षय ऊर्जा कंपनियों के शुल्क बोझ से एनबीएफसी पर दबाव

अभिजीत लेले
मुंबई, 6 जनवरी

बुनियादी ढांचा वित्त कंपनियों को अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में लगी पूंजी से संपत्ति गुणवत्ता पर पड़ने वाले अतिरिक्त दबाव के लिए कमर कसना पड़ा सकता है। ऐसा इसलिए है कि इन परियोजनाओं पर शुल्क जोखिम की तलवार लटक रही है। ये एनबीएफसी पहले से ही दबावग्रस्त ताप बिजली संपत्तियों के धीमे समाधान से मुश्किल का सामना कर रही हैं। यह अनुमान रेटिंग एजेंसी इक्रा ने जाहिर किए हैं।

सितंबर 2019 तक अक्षय ऊर्जा में लगी पूंजी 90,000 करोड़ रुपये अनुमानित है। भारत में बैंकों और इन्फ्रा एनबीएफसी का बुनियादी ढांचा में ऋण का दायरा सितंबर 2019 में समाप्त वित्त वर्ष 2020 की पहली छमाही में बढ़ा है। वित्त वर्ष 2019 में जहां बुनियादी ढांचा ऋण 19 फीसदी बढ़कर 21.1 लाख करोड़ रुपये रहा था यह वित्त वर्ष 2020 की पहली छमाही में मामूली बढ़कर 21.2 लाख करोड़ रुपये हो गया।

कुछ दक्षिणी राज्यों में शुल्क को लेकर अनिश्चितता के कारण ऋणदाताओं से रकम जुटाने वाली बिजली कंपनियों की रेटिंग में कमी आई है। अक्षय बिजली खंड में कम रेटिंग वाली कंपनियों की संख्या में इजाफा होने से बिजली क्षेत्र में रेटिंग में बढ़ोतरी और गिरावट वाली कंपनियों की संख्या का अनुपात वित्त वर्ष 2020 की पहली छमाही में घटकर एक से कम हो गई है। इक्रा ने कहा है कि रेटिंग में कमी आने से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे राज्यों में डिस्कॉम से भुगतान को लेकर तरलता के मुद्दों से जूझ रहे डेवलपरों का बोझ और बढ़ गया है।

आंध्र प्रदेश में पवन और सौर बिजली परियोजनाओं के लिए शुल्क मुद्दे के समाधान को लेकर अनिश्चितता पर भी चिंता बनी हुई है। वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 2019 के बीच यह अनुपात एक से अधिक था क्योंकि तब मुख्य तौर पर पवन और सौर खंड में अक्षय ऊर्जा इकाइयों की रेटिंग बढ़ाई गई थी।

इक्रा का कहना है कि सरकार और ऋणदाताओं की ओर से विभिन्न कदम उठाए जाने के बावजूद दबावग्रस्त ताप ऊर्जा संपत्ति के समाधान की प्रक्रिया धीमी है। दबावग्रस्त क्षमता के केवल 10 फीसदी का समाधान हो पाया है और 4 फीसदी का समाधान पहले हो चुका था लेकिन बाकी अभी भी दबावग्रस्त ही हैं। इस दिशा में केवल सकारात्मक बात यह है कि 20 फीसदी प्रभावित क्षमता को हाल ही में एनसीएलटी में स्वीकृत किया गया है। कुल मिलाकर करीब 38 फीसदी दबावग्रस्त क्षमता को एनसीएलटी में स्वीकृत किया गया है या उसके पास भेजा गया गया है। बाकी संपत्ति ऋणदाताओं द्वारा समाधान के अंतर्गत है।

ताप बिजली से जुड़े दबाव को पहले ही इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों ने पहचान लिया है। लेकिन अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में विपरीत परिस्थितियों के कारण अल्पावधि से मध्यावधि में बनने दबाव को लेकर चिंता बनी हुई है।

ताप बिजली क्षेत्र में अत्यधिक दबाव के कारण आईएफसी की संपत्ति गुणवत्ता में भी वित्त वर्ष 2016 से वित्त वर्ष 2018 के दौरान कमी आई है। इसमें बैंकों की ओर से दीर्घावधि संरचनात्मक मुद्दों और संपत्ति गुणवत्ता की समीक्षा की भी भूमिका है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि इसके बावजूद पिछले 18 महीनों में बढ़ती चूक की रफ्तार धीमी पड़ी है और संपत्ति गुणवत्ता रुझान दर्शाता है कि दबाव कम हो रहा है।

अतिरिक्त दबाव

- सितंबर 2019 तक अक्षय ऊर्जा में लगी पूंजी 90,000 करोड़ रुपये अनुमानित
- वित्त वर्ष 2019 में बुनियादी ढांचा ऋण 19 फीसदी बढ़कर 21.1 लाख करोड़ रुपये रहा था
- यह कर्ज वित्त वर्ष 2020 की पहली छमाही में मामूली बढ़कर 21.2 लाख करोड़ रुपये हो गया

'निर्विक' से मिलेगा देश के निर्यात को दम

पृष्ठ 1 का शेष

नवंबर में निर्यात में 0.32 फीसदी की गिरावट दर्ष की गई। इस तरह निर्यात में लगातार चौथे महीने और इस वित्त वर्ष में पांचवें महीने गिरावट आई।

फियो के महानिदेशक और मुख्य कार्याधिकारी अजय सहाय ने कहा, 'निर्यात क्रेडिट की दरों में कमी से निर्यात क्षेत्र को बहुत फायदा होगा क्योंकि इससे निर्यातकों को बेहतर ब्याज दरों के लिए माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी और व्यवस्था ज्यादा पारदर्शी होगी। इससे निर्यात चक्र या परिचालन चक्र की लागत में कमी आएगी। जो निर्यातक एक महीने में दो निर्यातक चक्र करते थे, वे अब तीन कर पाएंगे।'

ईसीआईएस में दावों के त्वरित निपटान की भी तैयारी की जा रही है। इसके लिए 30 दिन के भीतर 50 फीसदी अस्थायी भुगतान किया जाएगा। सहाय ने कहा कि निर्यात के लिए कम ब्याज दरों के अलावा निर्यातकों को बेहतर रेटिंग से भी फायदा मिलेगा क्योंकि ईसीआईएस को निर्यात प्रोत्साहन योजना बनाने पर विचार किया जा सकता है।

बैंकों को उम्मीद है कि इससे बैंक निर्यातकों को ऋण देने में दिलचस्पी दिखाएंगे। अधिकारियों ने कहा कि ईसीजीसी का लक्ष्य सालाना 3 लाख करोड़ रुपये कवरेज का है जो वित्त वर्ष के अंत तक कवरेज से बाहर थे। अतिरिक्त बोझ उठाने के लिए सरकार ईसीजीसी को सालाना 1,700 करोड़ रुपये देगी। वाणिज्य विभाग ने साफ किया है कि ईसीजीसी के दायरे में न केवल ऋण का मूलधन आएगा बल्कि चुकाया नहीं गया ब्याज भी आएगा।

बीएस सूडोकू 3632

2	4	5	8				6	
			1				7	
	1	8	9					
		3			8			6
	2	6				7	8	
4			7			3		
					2	8	4	
	9				1			
	5				7	2	1	3

परिणाम संख्या **3631**

9	7	2	3	1	4	6	8	5
5	3	8	6	9	7	4	1	2
6	1	4	2	5	8	9	7	3
8	2	3	4	7	6	1	5	9
4	5	6	9	8	1	3	2	7
7	9	1	5	2	3	8	6	4
2	6	5	8	3	9	7	4	1
1	8	9	7	4	5	2	3	6
3	4	7	1	6	2	5	9	8

कैसे खेलें?
हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

आसान ★★☆☆☆

क्षेत्रीय मंडियों के भाव

उत्तर प्रदेश | राजस्थान | पंजाब

कानपुर
गेहूं लूज 2205/2210, जौ 1770/1780, चावल मसूरी 2250/2300, चावल मोटा 2200/2250, सरसों 4650/4700, तिल सफेद 9600/9800, सोया (टीन) 1575/1625, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन)1600/1700,

लखनऊ
गेहूं दड़ा 2215/2220, गेहूं शरबती 2900/3000, चावल शरबती सेला 3750/3800, स्टीम 4300/4400, लालमती 3300/3400, चावल (सोना) 2950/3000

चंदौसी
(प्रति किलो): मैन्था ऑयल 1440, बोल्ड क्रिस्टल (12 नं.)1518, फ्लैक 1458, डीएमओ 1037, टरपीन लैस बोल्ड 1540

मुजफ्फरनगर
गुड़ (40 किलो): लड्डू 1160/1270, खुरपा 1040/1070,चाकू 1050/1200, रसकट 930/950, शक्कर 1200/1250, चीनी मिल डिली. (क्विं.) (जीएसटी अतिरिक्त): खतौली 3340, सिहोरा 3240, बुंदकी 3280, बुढ़ाना 3325,

हापुड़
गुड़-चीनी: चीनी हाजिर 3550/3600, गुड़ (प्रति 40 किलो) बाल्टी 1025/1050, तिलहन: सरसों (42 प्रतिशत कंडी.) 4625, खल: सरसों 2300/2400, बिनौला 2500/2650, चना छिलका 2100/2150,

जयपुर
अनाज: चावल डीबी 5600/5700, गेहूं (मिल) 2250/2260, मक्की 2250/2275, बाजरा 1940/1945, जौ 1800/1825, ग्वार लूज 3880/3900, ज्वार कैटलफीड 2400/2500, तेल-तिलहन: सरसों(मिल पहुंच) 4700/4725,

श्रीगंगानगर
गेहूं (ढेरी) 2100/2125, ग्वार 3800/3850, जौ 2190/2200,

जोधपुर
गेहूं 2100/2150, जौ 1800/1825, पोपकोन मक्की 4600/4700, ग्वार डिलीवरी (ऑलपेड) 4100/4150, ग्वारगम 7500/7600, बाजरा (गुजरात) 1990/2000, बाजरा (जयपुर) 2000/2010, चना 4350/4450, काबली चना 5100/6000, मूंग 6400/6500,

खन्ना
जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विं.): राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्वाइंट)127, राइसब्रान (अखाद्य) 124, खल सरसों 2100, डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद 1300, लाल 1300, कंटीन्यूअस 1300,

लुधियाना
दाल-दलहन: राजमां चित्रा 7500/8500, अरहर दाल 7500/8000, उड़द साबुत 7650/8600, उड़द धोया 9000/10000, छिलका 8800/9500, दाल मसूर 5900/6200, चनादाल 5400/5600,

अमृतसर
चावल: बासमती (1121 नं.) स्टीम 6100/6200, सेला 5600/5700, शरबती साधारण सेला 3800/3900, शरबती स्टीम 4100/4200, चावल 1509 सेला 5100/5200, धान: शरबती 2100/2150,

बठिंडा
रुई (प्रति मन): जे-34 पंजाब 4025/4065, हरियाणा 4000/4025, राजस्थान 3950/4025, खल (प्रति क्विं.): बिनौला 2600/2700, सरसों खल 2240/2250,

फाजिल्का
गेहूं 2275/2285, सरसों 4700/4800 रुई (प्रति मन): (जे-34) 4050/4100, कपास देशी 5100/5200, कपास नरमा (क्विं.) 5200/5400, बिनौला (टैक्सपेड): खल 2700/2750,

जालंधर
गेहूं दड़ा 2290/2300, चावल परमल कच्चा 2475/2500, से ला 2375/2400, मक्की यूपी 2325/2330, बिहार 2475/2500, दाल उड़द छिलका 9200/10400, चना देशी 5150/5250, दाल चना 5400/5600, काबली चना 5300/6200, राजमां चित्रा पुणे 7200/8600, चीन 7900/8400,

करनाल
गेहूं दड़ा 2220/2230, बासमती चावल 6500/6600, धान 1121 नं. 3000/3050, पूसा 1509 धान 2800/2825, शरबती धान 2150/2200, सेला (1509 नं.) चावल 5200/5300, स्टीम 6100/6200,

हिसार
ग्वार 3750/3800, जौ 1775/1780, सरसों 4300/4350, मूंग 6500/6700, गेहूं 2170/2180,

जींद
जीएसटी अतिरिक्त: गेहूं 2150/2180, आटा (प्रति 44 किलो) 1080/1090, मैदा 1190/1200, देशी घी (एक ली/जार) 400/500, रिफाइंड (टीन) 1600/1620,

भिवानी
जीएसटी अतिरिक्त: सरसों 4250/4300, खल बिनौला मोटी 2300/2400, बिनौला 2700/3200, सरसों तेल 9300/9350, गेहूं 2200/2225, ग्वार 3750/3800, बाजरा 1900/1950 *एनएनएस*

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 276

खाड़ी संकट में तैयारी

इराक दौरे पर गए ईरान के शीर्ष सैन्य अधिकारी कासिम सुलेमानी की अमेरिकी हमले में हुई हत्या ने पश्चिम एशिया में हालात बिगाड़ दिए हैं। इस इलाके के सशस्त्र संघर्ष के मुहाने पर पहुंच जाने से तेल कीमतों में अचानक उछाल आई है। ईरानी सेना की विशिष्ट इकाई कुद्स फोर्स के मुखिया के रूप में सुलेमानी क्षेत्रीय राजनीति में अहम स्थान रखते थे और खुद ईरान के भीतर वह काफी लोकप्रिय एवं सशक्त थे। इस हत्या के बाद खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। ऐसा होने पर अल्पावधि से लेकर मध्यम अवधि में तेल कीमतों के रुख को लेकर कोई भी अनुमान लगा पाना आसान नहीं है। एक तरफ तो अमेरिका का शेल तेल उत्पादन तेज है जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में मांग कमजोर है। वैसे बाजार किसी भी तरह जरूरत से ज्यादा आपूर्ति की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन समस्या यह है कि सीमित संघर्ष में भी तेल प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा सकता है। आपूर्ति शृंखला से हटा देने पर तेल की किल्लत पैदा हो सकती है जिससे अल्पावधि से मध्यावधि के भीतर तेल कीमतें चढ़ सकती हैं।

इस तरह भारत सरकार को तीन पहलुओं पर ध्यान देते हुए अपनी तैयारियां करनी होंगी। ये पहलू कई दशकों से एकसमान रहे हैं और पश्चिम एशिया में स्थिरता पर भारत की निर्भरता का कारण भी हैं। पहला बिंदु तेल की आपूर्ति से जुड़ा है। भारत को अपनी 84 फीसदी तेल जरूरतें आयात से पूरी करनी पड़ती हैं। इस तरह तेल कीमतों में उछाल न केवल घरेलू लागत परिस्थितियों बल्कि भुगतान संतुलन पर भी बड़ा अंतर डालता है। तेल कीमतें बढ़ने से पूरी अर्थव्यवस्था में स्वाभाविक तौर पर स्फीतिकारी दबाव पड़ेंगे। लिहाजा भारतीय रिजर्व बैंक को ब्याज दरें तय करते समय कहीं अधिक सजगता दिखाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अतीत में ऊंची तेल कीमतों ने बाह्य खाते को खासा कमजोर किया है। पश्चिम एशिया में 1991 में पैदा हुए ऐसे ही संकट के बाद भारत के समक्ष भुगतान संतुलन का संकट पैदा हुआ था जिसके बाद देश में उदारीकरण की शुरुआत हुई थी। आज 450 अरब डॉलर के साथ भारत का विदेशी मुद्रा भंडार काफी सुविधाजनक स्थिति में है और तेल कीमतों के मौजूदा स्तर पर रहने पर इससे अगले नौ-दस महीनों तक तेल आयात का इंतजाम हो सकता है। अगर तेल कीमतों में लगातार एवं तीव्र वृद्धि होती है तो फिर इस बफर में सेंध लग सकती है। हालांकि दो पहलू ऐसे हैं जो सरकार के लिए चिंता का विषय हैं। इन दोनों का ताल्लुक पश्चिम एशिया खासकर फारस की खाड़ी क्षेत्र में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय की मौजूदगी है। निश्चित रूप से उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। अतीत में भारत ने खाड़ी देशों में रहने वाले अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया था। पहले खाड़ी युद्ध के समय कुवैत और हाल में लीबिया से अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाया गया था। खाड़ी देशों से भारतीयों की सुरक्षित निकासी की योजना इस बार कहीं अधिक बड़े पैमाने पर अंजाम देनी होगी, वैसे ऐसी स्थिति आने की संभावना कम ही लग रही है।

हालांकि तनाव गहराने से आने वाली गिरावट के चलते बड़ी संख्या में अस्थायी कामगारों को भारत लौटना पड़ सकता है। ऐसा होने पर भारत को खाड़ी देशों से भेजा जाने वाला पैसा भी कम हो जाएगा। वर्ष 2016-17 में अकेले संयुक्त अरब अमीरात से 27 फीसदी विदेशी धन भारत में आया था और अन्य खाड़ी देशों का भी योगदान 27 फीसदी रहा था। भारत आने वाली आधी से भी अधिक विदेशी मुद्रा केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्यों में आती है। धन की आवक में बड़ी कमी होने से बाह्य खाते एवं इन राज्यों की अर्थव्यवस्था पर भी दबाव बढ़ेगा। लिहाजा भारत सरकार को खाड़ी के घटनाक्रम पर नजदीकी निगाह रखने के साथ अपनी तैयारियां भी रखनी होंगी।

अजय मोहंती

नए साल में कैसे होंगे भारत-अमेरिका संबंध

घरेलू मोर्चे पर भारत के हालात उसे चीन के बरक्स खड़ा करने की रणनीति की राह में रोड़े बन सकते हैं। नए साल में भारत-अमेरिकी संबंधों के भविष्य का जायजा ले रही हैं **अनीता इंदर सिंह**

नवनर्ष 2020 में भारत-अमेरिका संबंधों के लिए क्या परिदृश्य दिख रहा है? वर्ष 2006 में असैन्य परमाणु समझौते पर हुए हस्ताक्षर इस रिश्ते में उछाल की बानगी थी लेकिन वर्ष 2017 में डॉनल्ड ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद हालात बदलने लगे। वर्ष 1991 के बाद अमेरिकी आकलन में भारत की हैसियत ऊपर होने का सबसे बड़ा कारण आर्थिक प्रगति थी। करीब डेढ़ दशक तक इसकी उच्च वृद्धि दरों ने अमेरिका को यह यकीन दिला दिया था कि भारत को तेजी से उभरते सर्वाधिकारवादी चीन के बरक्स खड़ा किया जा सकता है। इसके अलावा एक बहुसांस्कृतिक लोकतंत्र के तौर पर भारत के स्थायित्व ने भी अमेरिका को प्रभावित किया, खासकर 1991 में यूगोस्लाविया और सोवियत संघ के पतन के बाद। हालांकि 2019 आने तक दुनिया के समक्ष यह साफ हो चुका है कि भारत की अर्थव्यवस्था गत छह वर्षों से पतन की राह पर है। इसके अलावा 2014 के बाद से ही सांप्रदायिक हिंसा की बढ़ती घटनाएं और नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लेकर देश भर में छिड़े विरोध प्रदर्शन राजनीतिक एवं सामाजिक ध्रुवीकरण को बयां कर रहे हैं। ये परिस्थितियां अपने लोकतंत्र की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं।

आर्थिक गिरावट और इससे जल्द उबरने की संभावना खारिज करने के बाद चीन के मुकाबले भारत को खड़ा करने के लिए ट्रंप की तरफ से पेश 'हिंद-प्रशांत' की अवधारणा भी सवालों के घेरे में आ गई है। बीते दशक में भारत और अमेरिका ने 15 अरब डॉलर से अधिक मूल्य वाले रक्षा सौदों पर दस्तखत किए हैं और हाल ही में अमेरिका ने एक अरब डॉलर मूल्य की नेवल गन बेचने की भी पेशकश रखी है। लेकिन भारत को चिढ़ाने वाली बात यह है कि एक औपचारिक सहयोगी नहीं होने से अमेरिका अब भी उसे संवेदनशील सैन्य तकनीक देने से मना कर देता है। संप्रभुता कहती है कि भारत को रूस से एस-400 मिसाइलें खरीदने का हक है, वहीं इस हवाई सुरक्षा प्रणाली के चलते अमेरिका के साथ नजदीकी सैन्य संबंध अवरुद्ध हो जाते हैं। अमेरिका रूस को अपनी सुरक्षा के लिए एक खतरे के तौर पर देखता है। अगर एक गठबंधन का अभाव अपनी सामरिक स्वायत्तता बनाए रखने की भारतीय प्रतिबद्धता को दर्शाता है तो यह अमेरिका को भारत के साथ संबंधों की व्यवहार्यता को लेकर संदिग्ध बना देता है।

कारोबारी मुद्दे भी उनके रिश्ते में अहम हैं। भारत की लालफीताशाही और संरक्षणवादी शुल्क अमेरिका को नागवार गुजरते हैं। ये मुद्दे एक व्यापारिक साझेदार के तौर पर भारत की चमक फीकी कर देते हैं। अमेरिकी निर्यात का महज 2.1 फीसदी ही भारत आता है और 2.2 फीसदी आयात भारत से होता है। वहीं भारतीय आयात का 15 फीसदी अमेरिका से आता है और उसके निर्यात का 16 फीसदी अमेरिका को जाता है। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के पतनोन्मुख होने के बीच चीन ने अपनी बेल्ट एवं सड़क पहल (बीआरआई) का विस्तार दुनिया भर में कर अपनी आर्थिक प्रगति का प्रदर्शन किया है। यूरोपीय संघ के कई सदस्य देशों और भारत के सारे पड़ोसियों ने बीआरआई का हिस्सा बनना स्वीकार कर लिया है। चीन के वित्तीय घूंसे ने उसे इन अर्थव्यवस्थाओं में सबसे बड़े निवेशक के तौर पर स्थापित कर दिया है। यह म्यांमार और बांग्लादेश को सबसे बड़ा हथियार विक्रेता भी है। हिंद महासागर में उसकी बढ़ती मौजूदगी एक प्रभावशाली दक्षिण एशियाई ताकत के तौर पर भारत की हैसियत के समक्ष मुश्किल सवाल खड़े करता है।

घरेलू मोर्चे पर सीएए पारित होने के बाद देश भर में उठे विरोध के स्वरों ने भारत की धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक छवि को लेकर अमेरिका में बहुतों को आशंकित कर दिया है। उसके पहले भी अमेरिकी विदेश विभाग ने गत वर्ष जून में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के समय भारत में धार्मिक असहिष्णुता बढ़ी है। भारत ने इसका प्रतिवाद करते हुए कहा था कि किसी विदेशी सरकार को उसके अंदरूनी मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है।

वॉशिंगटन में दिसंबर में हुई 2प्लस2 बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पिओ ने कहा कि अमेरिका हर जगह अल्पसंख्यकों एवं धार्मिक अधिकारों के संरक्षण को लेकर फिक्रमंद रहता है। उन्होंने हिंद-प्रशांत भागीदारी में विश्वास जताते हुए कहा कि यह सहयोग लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है।

अमेरिकी अधिकारियों के विचार एक-दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। पॉम्पिओ का बयान घरेलू तनावों के चलते भारत पर ट्रंप प्रशासन की तरफ से कोई भी दबाव डालने की बात नकारता नजर आया लेकिन अमेरिकी सांसदों का रवैया कुछ अलग कहानी ही कहता है। अगस्त के बाद कश्मीर के हालात और नागरिकता कानून के विरोध में उठे विरोध से निपटने के लिए किए गए ताकत के इस्तेमाल का हवाला देते हुए अमेरिकी कांग्रेस ने धर्मनिरपेक्षता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर सवालिया निशान लगाए हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी अल्पसंख्यकों को समान अधिकार देने का मुद्दा उठाया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कश्मीर पर चर्चा के लिए अमेरिकी संसद की विदेश समिति से मिलने से मना कर दिया तो यही बात उठी कि मानवाधिकार का मुद्दा उठाने वाले अमेरिकी सांसद ऐसी हरकत की उम्मीद किसी तानाशाही सरकार से करते हैं, भारत से नहीं।

सामरिक भागीदारी के बावजूद भारत और अमेरिका का रिश्ता वर्ष 2020 में हिलोरें मारती तरंगों से ही गुजरेगा। लेकिन भारत और चीन के बीच आर्थिक फासला होने से हिंद-प्रशांत के लिए ट्रंप की योजना में भारत की अहमियत को लेकर सवाल खड़े होते हैं। चीन की प्रति व्यक्ति जीडीपी भारत की तुलना में चार गुने से भी अधिक है। इसी तरह चीन का 177.6 अरब डॉलर का रक्षा बजट भारत का तिगुना है। जहां चीन वर्ष 2050 तक विश्व स्तरीय सेना बनाने की मंशा रखता है, वहीं भारत को अपने सशस्त्रबलों को आधुनिक बनाना भी मुश्किल हो रहा है।

अमेरिका पर अपनी आर्थिक एवं सैन्य निर्भरता से भारत जहां जलता है वहीं अमेरिका को इससे कोफ्त होती है। ट्रंप प्रशासन समृद्ध सहयोगी पसंद करता है क्योंकि इस तरह वे साझा खतरों का सामना बेहतर ढंग से कर सकते हैं।

नए साल की शुरुआत में भारत की लोकतांत्रिक स्थिरता एवं आर्थिक प्रगति अनिश्चित नजर आ रही है। भले ही नागरिकता कानून के खिलाफ हो रहे व्यापक प्रदर्शन रोजगार के मौके कम होने से उपजे गुस्से को भी बयां करते हैं लेकिन सरकार आर्थिक एवं सामाजिक-राजनीतिक संकट से उबरने के लिए वित्तीय एवं मानव संसाधनों के इस्तेमाल का कोई संकेत नहीं दिखा रही है। इसके बजाय नागरिकता कानून पर अमल की दिशा में बढ़ना यह दिखाता है कि वह धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र से दूर होने की कोशिश से अस्थिरकारी संघर्षों के पनपने की चेतावनी को नजरअंदाज करती है।

हिंद महासागर में भारत की सामरिक स्थिति ऐसी है कि अमेरिका उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता है। लेकिन वर्ष 2020 यह बताएगा कि क्या घरेलू स्तर पर आर्थिक एवं राजनीतिक मुश्किलों में घिरा भारत अमेरिका के साथ सामरिक सहयोग के लिहाज से बेमेल है या दोनों देशों के बीच करीबी सामरिक संबंध संभव हैं?

(लेखिका सेंटर फॉर पीस ऐंड कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्यूशन, नई दिल्ली की संस्थापक प्रोफेसर हैं)

देश के बुनियादी विकास में तेजी की तैयारी

दिल्ली डायरी

ए के भट्टाचार्य

बीते वर्ष के अंतिम दिन एक संवाददाता सम्मेलन में टास्क फोर्स ऑन नैशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन फॉर 2019-25 की रिपोर्ट जारी करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दो महत्त्वपूर्ण संदेश दिए। पहला, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उन्हें 2020-21 का आम बजट पेश करने से एक महीना पहले मीडिया से मिलने में कोई परेशानी नहीं है। दूसरा, यह कि उन्हें अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए देश को यह बताने में देरी का कोई कारण नजर नहीं आता कि वरिष्ठ सरकारी अधिकरियों के एक समूह ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश को पटरी पर लाने के लिए क्या सिफारिश की है।

अमूमन बजट से पहले वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय मीडिया से दूर ही रहते हैं। ऐसा कम ही होता है कि वित्त मंत्रालय का कोई अधिकारी बजट पेश होने से चार हफ्ते पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, वित्त मंत्री तो दूर की बात है। बजट को लेकर गोपनीयता बरती जाती है और बजट में की जाने वाली घोषणाओं को गोपनीय रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाते हैं। इसलिए, बजट से एक महीना पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस से परहेज किया जाता है। ऐसी स्थिति में बजट से एक महीना पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद यही रहा होगा कि सभी को यह स्पष्ट संदेश दिया जाए कि सरकार बुनियादी ढांचे में ज्यादा निवेश को लेकर गंभीर है।

हालांकि, इस प्रक्रिया में एनआईपी टास्क फोर्स की रिपोर्ट में 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट के बारे में कुछ अहम संकेत दिए होंगे। उदाहरण के लिए टास्क फोर्स के अनुमान के मुताबिक 2019-20 में सकल घरेलू अनुपात (जीडीपी) की नॉमिनल वृद्धि करीब 8 फीसदी रहेगी जबकि पहले इसके 12 फीसदी रहने का अनुमान जताया गया था। नॉमिनल संदर्भ में 2019-20 में जीडीपी के 205.37 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है जो 2018-19 में 190 लाख करोड़ रुपये थी। टास्क फोर्स के मुताबिक नॉमिनल जीडीपी के 2020-21 में 10.5 फीसदी और 2021-22 में 12 फीसदी की रफ्तार से बढ़ने का अनुमान है।

आर्थिक मामलों के सचिव अतनु चक्रवर्ती टास्क फोर्स के प्रमुख हैं। नीति आयोग के मुख्य कार्याधिकारी और वित्त मंत्रालय तथा दूसरे प्रशासनिक मंत्रालयों के सचिव इसके सदस्य हैं। तो क्या टास्क फोर्स के आंकड़ों से आपको मौजूदा आर्थिक वृद्धि परिदृश्य की थाह नहीं मिलती है जिसमें अगले वर्ष का बजट बनाया जा रहा है? हर कोई जानता है कि आर्थिक वृद्धि की गति धीमी पड़ रही है लेकिन इस रिपोर्ट के जारी होने से पहले सरकार में किसी ने भी नहीं कहा था कि 2019-20 में नॉमिनल वृद्धि केवल 8 फीसदी रहेगी। जाहिर है कि सरकार के कर राजस्व पर इसका प्रतिकूल असर होगा।

> एनआईपी टास्क फोर्स ने अगले साल बुनियादी क्षेत्र के लिए सरकारी फंड में भारी बढ़ोतरी का सुझाव दिया है। क्या सरकार बुनियादी क्षेत्र के लिए ज्यादा वित्तीय खर्च की मांग को नजरदांज कर सकती है?

एनआईपी टास्क फोर्स की रिपोर्ट से यह पता भी चलता है कि बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए अगले बजट में क्या हो सकता है। 2018-19 में बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार की सकल बजट सहायता 1.39 लाख करोड़ रुपये रही थी जो विभिन्न मदों के तहत सभी पूंजीगत व्यय के लिए सरकार की कुल बजट सहायता का 44 फीसदी है। 2019-20 में कुल पूंजीगत खर्च के लिए सकल बजट सहायता में बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए बजट सहायता का हिस्सा 45 फीसदी यानी 1.53 लाख करोड़ रुपये है। टास्क फोर्स के मुताबिक 2020-21 में बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए 1.86 लाख करोड़ रुपये के बजट सहायता की जरूरत होगी। अगर अगले वर्ष भी 44-45 फीसदी हिस्सेदारी बरकरार रहती है तो पूंजीगत व्यय के लिए केंद्र सरकार की सकल बजट सहायता 22 फीसदी बढ़कर 4.13 लाख करोड़ रुपये बढ़नी चाहिए। 22 फीसदी से कम बढ़ोतरी का मतलब होगा कि वित्त मंत्रालय ने अपनी समिति की रिपोर्ट ही स्वीकार नहीं की है।

एनआईपी टास्क फोर्स का साथ ही कहना है कि बुनियादी क्षेत्र के लिए सरकार का कुल खर्च 2020-21 में 21 फीसदी बढ़कर 4.58 लाख करोड़ रुपये होना चाहिए जो 2019-20 में 3.77 लाख करोड़ रुपये है। यह एक महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य है क्योंकि 2019-20 में बुनियादी क्षेत्र के लिए कुल व्यय में केवल 6.5 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी।

सरकार के कुल पूंजीगत खर्च (भारतीय रेल सहित सार्वजनिक इकाइयों की आंतरिक और अतिरिक्त बजट संसाधनों सहित) में बुनियादी क्षेत्र पर कुल सरकारी खर्च का हिस्सा 38 से 43 फीसदी के बीच रहा है। अगर यह हिस्सा 2020-21 में बरकरार रहता है तो अगले साल के बजट में सरकार के कुल पूंजीगत व्यय में 21 फीसदी बढ़ोतरी के साथ 10.65 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान होना चाहिए।

इन आंकड़ों से साफ है कि एनआईपी टास्क फोर्स ने अगले साल बुनियादी क्षेत्र के लिए सरकारी फंड में भारी बढ़ोतरी का सुझाव दिया है। क्या सरकार बुनियादी क्षेत्र के लिए ज्यादा वित्तीय खर्च की मांग को नजरदांज कर सकती है? और क्या बजट से कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनआईपी टास्क फोर्स की रिपोर्ट जारी करने के फैसले का मकसद सरकार के भीतर प्रभावशाली वर्गों पर ज्यादा खर्च करने की जरूरत स्वीकार करने और राजकोषीय समेकन लक्ष्यों के लिए ज्यादा दबाव डालना है।

कानाफूसी

मीठा और गर्म प्रचार

दिल्ली में चुनाव नजदीक आ गए हैं, इसलिए टिकट उम्मीदवारों ने अनोखे उपहारों से मतदाताओं को लुभाना शुरू कर दिया है। ऐसे ही एक नेता भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के आजाद सिंह हैं, जो मतदाताओं को गुड़ और कैलेंडर बांट रहे हैं। हर कोई यही कहेगा कि ये इस समय के लिहाज से सबसे उपयुक्त तोहफे हैं क्योंकि नया साल शुरू हुआ है और पिछले पखवाड़े में मौसम अब तक का सबसे ठंडा रहा है। गुड़ और कैलेंडर को कपड़े के थैले में पैक किया गया है, जिस पर फोन नंबर लिखे हैं। यहां कपड़े के थैले का जिक्र करना इसलिए अहम है क्योंकि थैले पर छपा है- 'प्लास्टिक को ना कहें'। पिछले सप्ताह ये तोहफे वसंज कुंज में बांटे गए। सिंह के समर्थक तोहफे को लेने से इनकार करने वालों को मनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। जो लोग घर पर नहीं थे, उन्हें भी ये थैले अपने दरवाजे पर टंगे मिले।

चौथी बार खुली किस्मत

पश्चिम बंगाल जैसे राज्य इस बात से खफा हैं कि उन्हें इस साल की गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने की मंजूरी नहीं दी गई। लेकिन गृह मंत्रालय के तहत आने वाले एक विशेष बल राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) को अपने करीब 15 साल के इतिहास में पहली बार सूची में रखा गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एनडीआरएफ ने चौथी बार झांकी सौंपी थी। पहले तकनीकी या अन्य वजहों से जगह बनाने में नाकाम रहने के बाद झांकी को तैयार कर रही टीम इस बार अपनी किस्मत को जानने के लिए उत्सुक थी। जब पिछले शुक्रवार को 22 भागीदारों की सूची की घोषणा की गई तो उनके पास पास खुशी मनाने का मौका था। झांकी में बचाव कार्यों के दौरान बल की सतर्कता और त्वरित प्रतिक्रिया दिखाई जाएगी।

आपका पक्ष

विश्व को अमेरिका-ईरान टकराव से घाटा

हाल में अमेरिका ने ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी को ड्रोन हमले में मार गिराया। इसके बाद अंतराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी हो गई। ईरान कच्चे तेल का बड़ा निर्यातक देश है और विश्व के कई देश ईरान से कच्चा तेल आयात करते हैं। भारत भी उससे कच्चे तेल का आयात करता है। इससे पहले अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाया था और अन्य देशों को ईरान से तेल आयात करने को मना किया था। इसके बाद तेल कीमतों में उछाल आई थी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ने से इसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ता है। भारत में भी पेट्रोल के दाम तेजी से बढ़ गए। इसके अलावा भारत का ईरान को आयात निर्यात भी प्रभावित हुआ है। भारत का कारोबार अमेरिका और ईरान दोनों देशों से होता है। भारत के लिए दोनों देश काफी महत्त्व रखते हैं। कारोबार के मामले में भारत के ईरान से घनिष्ठ व्यापारिक संबंध है। अमेरिकी प्रतिबंध के बाद भी ईरान भारतीय मुद्रा में तेल निर्यात पर सहमत हो गया था। अगर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव गंभीर स्थिति तक पहुंच जाता है तो इससे विश्व के कई देशों को भी नुकसान होगा। अमेरिकी हमले के बाद विश्व युद्ध छिड़ने की संभावनाएं बढ़ने लगी हैं। इस समय सभी देशों को संयम से काम लेना चाहिए और युद्ध के हालात नहीं बने इसपर सोचना चाहिए। युद्ध से देश को तो नुकसान होता है बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी इसका असर पड़ता है। आज कई देश परमाणु संपन्न देश हैं। ऐसे में अगर एक भी परमाणु बम इस्तेमाल किया जाता है तो इसका असर पूरे विश्व पर पड़ सकता है जैसा कि जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर पड़ा था। अत: विश्व के सभी देशों को अमेरिका और ईरान के बीच टकराव को रोकने की दिशा में विशेष पहल करनी चाहिए और दोनों देशों के बीच शांति बहाल करने का संदेश देना चाहिए।

अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए अन्य देशों को आगे आना चाहिए

गौरव कुमार, नई दिल्ली

बजट से मिलेगी बदलाव की उम्मीद

सरकार इस आम बजट को इस अनुमान के आधार पर तैयार कर सकती है कि इस साल में देश की विकास दर में अच्छी बढ़ोतरी हो। साल 2020 का बजट प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए काफी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि सरकार देश को आर्थिक सुस्ती से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। साल 2020 में विकास दर 6 से 6.5 फीसदी विकास होने का अनुमान है। अर्थव्यवस्था में तेजी से वापसी के संकेत दिख रहे हैं। शेयर बाजार चालू वित्त वर्ष में मुनाफे में 25 फीसदी वृद्धि की उम्मीद कर रहा है। अगर यह अनुमान सही साबित हुआ तो नए साल में शेयर बाजार नए शिखर पर पहुंच सकता है। सरकार को आम लोगों के साथ निवेशकों की धारणा भी सुधारने की जरूरत है। अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यापार युद्ध सुलझाने की दिशा में भी बाजार में तेजी आ सकती है। इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में होने वाले उतार-चढ़ाव का भी असर देखने को मिल सकता है।

अमित जायसवाल, गोरखपुर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

बेहतर नमी से चालू रबी सीजन में फसलों की रिकॉर्ड बुआई

बारिश ने बढ़ाया रबी फसलों का रकबा

सुशील मिश्र
मुंबई, 6 जनवरी

चालू रबी सीजन में फसलों की रिकॉर्ड बुआई हुई है। रबी सीजन की करीब सभी फसलों की बुआई पिछले साल से ज्यादा हुई है। देशभर में 3 जनवरी तक रबी फसलों की बुआई 600 लाख हेक्टेयर के रकबे को पार कर गई है, जो सामान्य बुआई के आंकड़ों से भी ज्यादा है। पिछले रबी सीजन की अपेक्षा बुआई क्षेत्र 38.37 लाख हेक्टेयर अधिक है। खेतों में बेहतर नमी के कारण लगभग सभी राज्यों और रबी सीजन की सभी फसलों की बुआई पिछले साल से बेहतर हुई है। चालू सीजन में फसलों की बुआई लक्ष्य के पार जा सकती है।

वर्ष की शुरुआत में कृषि मंत्रालय की तरफ से फसल बुआई के जो आंकड़े आए हैं वह उम्मीद से भी बेहतर हैं। चालू रबी सीजन 2019-20 में 3 जनवरी तक देशभर में कुल 600.32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों की बुआई हो चुकी है जबकि पिछले साल इसी अवधि में 561.95 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई हुई थी। इस समय तक रबी फसलों की बुआई का सामान्य रकबा 573.63 लाख हेक्टेयर है अर्थात चालू सीजन में फसलों की बुआई पिछले साल की अपेक्षा 38.37 और सामान्य रकबे से 26.69 लाख हेक्टेयर अधिक हुई है।

कृषि मंत्रालय के मुताबिक चालू फसल सीजन की शुरुआत में देश के अधिकांश हिस्सों में बारिश हुई है। मॉनसून सीजन में भी देश के अधिकतर हिस्सों में अच्छी बारिश हुई थी। देर तक बारिश होने से देश के ज्यादातर राज्यों में मिट्टी में नमी मौजूद है। इससे किसानों ने फसलों की जमकर बुआई की। यह बुआई अभी भी जारी है जिसे देखते हुए माना जा रहा है कि इस सीजन में फसलों की बुआई कृषि मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य 633.98 लाख हेक्टेयर को भी पार कर जाएगी।

रबी सीजन की सबसे प्रमुख फसल गेहूं की इस बार रिकॉर्ड बुआई हुई है। गेहूं की बुआई रबी सीजन के निर्धारित लक्ष्य और सामान्य रकबे दोनों को पार कर चुकी है। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 3 जनवरी तक देशभर में 312.81 लाख हेक्टेयर गेहूं की बुआई हुई है, जबकि पिछले रबी सीजन में इस समय तक 286.23 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुआई हुई थी। 3 जनवरी को खत्म हुए सप्ताह तक गेहूं का सामान्य रकबा 288.68 लाख हेक्टेयर रहा, जबकि इस साल रबी सीजन के दौरान गेहूं की बुआई का कुल लक्ष्य 305.58 लाख हेक्टेयर तय किया गया था। चालू सीजन में 3 जनवरी तक गेहूं का रकबा पिछले साल की सामान्य अवधि के मुकाबले 26.58 लाख हेक्टेयर और सामान्य रकबे से 24.13 लाख हेक्टेयर अधिक है।

राज्यों से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक 2019 के खत्म होने तक देशभर में दलहन फसलों की बुआई 146.24 लाख हेक्टेयर में हुई, जबकि पिछले साल इस समय तक 142.22 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में दलहन फसलों की बुआई हुई थी। मोटे अनाजों की बुआई भी पिछले साल से 5.58 लाख हेक्टेयर अधिक हुई है। देश में अभी तक 49.40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मोटे अनाजों की बुआई हुई है जबकि पिछले साल इस समय तक 43.82 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी।

तिलहन फसलों का रकबा भी पिछले साल से थोड़ा आगे निकल चुका है। तिलहन फसलों का रकबा पिछले साल के 75.71 लाख हेक्टेयर की अपेक्षा चालू रबी सीजन में 75.72 लाख हेक्टेयर हो चुका है। रबी सीजन के चावल की रोपाई 16.16 लाख हेक्टेयर में हुई है जो पिछले सीजन में इस समय तक 13.98 लाख हेक्टेयर में हुई थी।

रबी सीजन में फसलों की बुआई

फसल	2019-20	2018-19	बढ़त
गेहूं	312.81	286.23	26.58
दलहन	146.24	142.22	04.02
मोटे अनाज	49.40	43.82	05.58
तिलहन	75.72	75.71	00.01
चावल	16.16	13.98	02.17
कुल	600.32	561.32	38.37

नोट- बुआई क्षेत्र लाख हेक्टेयर में (3 जनवरी 2020 तक), स्रोत- कृषि मंत्रालय

गेहूं की रिकॉर्ड बुआई

- रबी सीजन की सबसे प्रमुख फसल गेहूं की इस बार रिकॉर्ड बुआई हुई है
- रबी सीजन के निर्धारित लक्ष्य और सामान्य रकबे को पार कर गया गेहूं

चीनी उद्योग को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए महाकुंभ

मुंबई में 11-12 जनवरी को शुगर कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन

बीएस संवाददाता
मुंबई, 6 जनवरी

पिछले कई वर्षों से चुनौतियों का सामना कर रहे भारतीय चीनी उद्योग को इस साल सुधार की उम्मीद नजर आने लगी है। उत्पादन कम होने, विदेशी बाजार में मांग बढ़ने और निर्यात कोटा में बढ़ोतरी के साथ एथनॉल के विकल्प को चीनी उद्योग की किस्मत संवारने वाले संकेत माना जा रहा है। बदले परिवेश में चीनी उद्योग को शीर्ष पर ले जाने के लिए चीनी कारोबारी घरेलू नीतियों के साथ वैश्विक रणनीति बनाने की योजना तैयार कर रहे हैं।

ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन 11-12 जनवरी को मुंबई में एआईएसटीए शुगर कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन कर रही है। एसोसिएशन के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी के मुताबिक इस बैठक में भारत के चीनी एवं एथनॉल क्षेत्र से संबंधित कई महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इनमें गन्ने का मूल्य, किसानों को सही समय पर भुगतान, चीनी निर्यात की संभावनाएं, वैश्विक आपूर्ति की मांग और मूल्य का परिदृश्य, गैसोलिन को एथनॉल से मिलाने की नीति व विनियमन शामिल है।

विठलानी कहते हैं कि इस बैठक का विशेष महत्त्व है क्योंकि चीनी उद्योग भारत के ग्रामीण क्षेत्र के लिए महत्त्वपूर्ण है। चीनी मिलें ग्रामीण भारत में हैं और लगभग पांच लाख ग्रामीणों को रोजगार देती है साथ ही गन्ने की खेती पर निर्भर 50 लाख लोगों को प्रत्यक्ष सहयोग दे रही है। उपभोक्ता तक पहुंचने से पहले चीनी की वैल्यू चेन लाखों लोगों को अपने में शामिल करती है।

चीनी उद्योग और कृषि दोनों के लिए जरूरी है इसीलिए हर क्षेत्र के वरिष्ठ व जानकारों को इसमें शामिल किया गया है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री रावसाहब दानवे पाटिल, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मंत्री जयंत पाटिल, दिलीप वालसे और राजेश टोपे, गुजरात सरकार की तरफ से ईश्वर सिंह पटेल सरकार का पक्ष रखेंगे, वहीं केंद्र सरकार के सरकार एवं कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के चेयरमैन प्रोफेसर विजय पॉल शर्मा, भारत सरकार के संयुक्त सचिव (चीनी) कमल दत्ता, एनएसआई कानपुर के निदेशक नरेंद्र मोहन इत्यादि अधिकारी सरकारी नीतियों की स्पष्ट रुपरेखा कारोबारियों को बताएंगे।

इस आयोजन के सह-आयोजक नेशलन फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज, वेस्टर्न इंडिया शुगर मिल्स एसोसिएशन, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज फेडरेशन, गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज फेडरेशन, बंबई शुगर मर्चेंट्स एसोसिएशन, गुजरात शुगर एजेंट्स एसोसिएशन, कोल्हापुर खरड़-सांगली शुगर मर्चेंट्स एसोशिएशन, मैरेक्स स्पेक्ट्रॉन, लंदन और अल खलीज़ शुगर्स दुबई, ट्रॉपिकल रिसर्च सर्विसेज, अमेरिका व ब्रिटेन के चीनी कारोबारी संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल होगें।

शुगर कॉन्क्लेव में एथनॉल क्षेत्र से संबंधित कई महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर होगी चर्चा

अंतरराष्ट्रीय और घरेलू भाव

As on Jan 6	International Price	International %Chg#	Domestic Price	Domestic %Chg#
METALS ($/tonne)				
Aluminium	1,758.0	3.3	2,015.6	1.3
Copper	6,077.0	8.5	6,449.8	8.9
Nickel	13,740.0	-23.3	14,526.0	-20.8
Lead	1,889.5	-12.0	2,168.5	3.2
Tin	16,750.0	2.4	17,723.1	0.9
Zinc	2,284.0	-2.6	2,557.7	-1.5
Gold ($/ounce)	1,576.9*	4.8	1,758.7	5.2
Silver ($/ounce)	18.4*	5.1	20.7	4.7
ENERGY				
Crude Oil ($/bbl)	69.8*	18.8	66.0	13.2
Natural Gas ($/mmBtu)	2.2*	-8.5	2.2	-9.1
AGRI COMMODITIES ($/tonne)				
Wheat	192.9	13.8	314.7	6.9
Maize	188.1*	4.2	329.2	9.6
Sugar	359.7*	4.1	484.7	-1.6
Palm oil	787.5	50.7	1,209.3	42.4
Rubber	1,643.2*	17.9	1,834.9	7.9
Coffee Robusta	1,344.0*	4.0	1,848.8	-6.4
Cotton	1,528.0	14.4	1,613.3	-1.3

* As on Jan 06, 20 1800 hrs IST, # Change Over 3 Months, Conversion rate 1 USD = 71.9& 1 Ounce = 31.1032316 grams.

Notes:
1) International metals, Indian basket crude, Malaysia Palm oil, Wheat LIFFE and Coffee Karnataka robusta pertains to previous days price. 2) International metal are LME Spot prices and domestic metal are Mumbai local spot prices except for Steel.
3) International Crude oil is Brent crude and Domestic Crude oil is Indian basket. 4) International Natural gas is Nymex near month future & domestic natural gas is MCX near month futures. 5) International Wheat, White sugar & Coffee Robusta are LIFF E future prices of near month contract. 6) International Maize is MATIF near month future, Rubber is Tokyo-TOCOM near month future and Palm oil is Malaysia FOB spot price. 7) Domestic Wheat & Maize are NCDEX future prices of near month contract, Palm oil & Rubber are NCDEX spot prices. 8) Domestic Coffee is Karnataka robusta and Sugar is M30 Mumbai local spot price. 9) International cotton is Cotton no.2-NYBOT near month future & domestic cotton is MCX Future prices near month tures.

Bloomberg chartMaker — Compiled by BS Research Bureau

एमसीएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	53.2	21392
Oil and Oilseeds	375.1	60278
Spices	1.9	13
Metal(Jan 03)		
Metal- non ferrous	4961.7	47159
Metal- precious	17163.8	436
Oil and gas(Jan 03)		
Gas	3022.1	50259
Oil	24138.1	2315

एनसीडीईएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	171.6	116416
Grains	248.1	105350
Oil and Oilseeds	1519.8	539790
Others	181.5	71230
Pulses	107.2	38300
Spices	80.0	28236

एमसीएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Crude Oil (Jan 17)	4499.0	3.6
Gold (Feb 05)	40112.0	2.1
Gold Guinea (Jan 31)	31872.0	1.9
Gold Petal (Jan 31)	3987.0	1.7
Aluminium Mini (Jan 31)	139.9	1.6
Silver (Mar 05)	47527.0	1.1
Losers (* % Change)		
Crude Palm Oil (Jan 31)	794.3	-2.8
Nickel (Jan 31)	1019.9	-2.4
Cardamom (Jan 15)	4045.3	-1.4
Aluminium (May 29)	138.8	-0.5
Copper (Jan 31)	441.8	-0.5
Mentha Oil (Jan 31)	1286.1	-0.4

एनसीडीईएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
CastorSeed New-Disa (Jan 20)	4228.0	0.4
Shankar Kapas-Rajkot (Apr 30)	1123.5	0.3
Losers (* % Change)		
Turmeric Nizamabad (Mar 20)	6278.0	-3.9
Soyabean Indore (Jan 20)	4190.0	-3.9
Mustard Seed Rape Oil (Jan 20)	4483.0	-2.8
Ref Soy Oil-IDR-2016 (Jan 20)	912.4	-2.7
Coriander-Kota (Jan 20)	6514.0	-2.6
GuarGum 5T-Jodhpur (Jan 20)	7306.0	-2.0
CottonSeed Oil-Akola (Jan 20)	2098.0	-1.9
Bajra (Jan 20)	2025.0	-1.1
Guar Seed 10 (Jan 20)	4078.0	-1.0
Chana-Bikaner (Jan 20)	4461.0	-0.8

एमसीएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Cotton-Rajkot (Jan 31)	19730.0	3.3
Cardamom Vandanmedu (Jan 15)	4045.3	2.1
Kapas Surendranagar (Feb 28)	1070.0	1.9
Discount over spot price (In %)		
Menthol Oil Chandaus (Jan 31)	1286.1	-8.2
Aluminium Mum (May 29)	138.8	-3.4
Copper Mum (Jan 31)	441.8	-3.4
Alumini-Mumbai (Jan 31)	139.9	-2.6
Zinc Mini Mumbai (Jan 31)	180.2	-2.4
Gold Petal-Mumbai (Jan 31)	3987.0	-2.3
Gold Ahm (Feb 05)	40112.0	-1.4
Lead Min Mumbai (Jan 31)	152.2	-1.2
Lead Mum (May 29)	152.3	-1.1

एनसीडीईएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Turmeric Nizamabad (Mar 20)	6278.0	2.3
Crude Palm Oil Kandl (Jan 31)	830.7	1.6
Bajra-Jaipur (Jan 20)	2025.0	1.5
Paddy-Basmati-Karnal (Jan 20)	3309.0	0.3
Bajra-Delhi (Jan 20)	2025.0	0.2
29 mm Cotton-Rajkot (Jan 20)	19000.0	0.1
Discount over spot price (In %)		
Coriander-Kota (Jan 20)	6514.0	-5.3
Soy Bean Indore (Jan 20)	4190.0	-3.1
Maize-Sangli (Jan 20)	2019.0	-2.6
Moong-Merta City (Jan 20)	7396.0	-2.0
Barley Jaipur (Jan 20)	2198.0	-0.9

कल का हाजिर भाव

औद्योगिक

Metals .....Mumbai
Aluminium utensil scrap /kg 106.....(106)
Aluminium ingots /kg 145.....(142)
Brass sheet cutting /kg 330.....(328)
Brass utensil scraps/kg 312.....(312)
Copper heavy scrap /kg 431.....(431)
Copper utensil scraps/kg 402.....(402)
Copper wire bar /kg 464.....(463)
Lead ingots /kg 156.....(156)
Nickel Cathodes /kg 1045.....(1040)
Tin slabs /kg 1275.....(1280)
Zinc slabs /kg 184.....(183)
Source:Bombay Metal Exchange

Cotton .....Mumbai
Bengal Deshi /Qtl 10320.....(10320)
DCH - 32 /Qtl 11332.....(11276)
Jaydhar /Qtl 9926.....(9926)
Shankar- 6 /Qtl 11135.....(11079)
Source:Cotton Association of India

Oil .....Mumbai
Castor FSG /10kg 895.....(894)
Castor Comm /10kg 885.....(884)
Ricebran oil/10kg -.....(820)
Groundnut oil /10kg 1150.....(1180)
Linseed oil /10kg -.....(990)
Karanji /10kg -.....(800)
Palm oil /10kg 874.....(882)
Sunflower exp ref /10kg 930.....(940)
Sunflower oil exp /10kg 900.....(900)
Soyabean ref / 10kg 920.....(935)
Source:Bombay Commodity Exchange

सॉफ्ट

Sugar .....Mumbai
Mumbai M-30 /Qtl 3392-3582 .....(3362-3582)
Source:Bombay Sugar Merchants Association

ऊर्जा

Crude Brent-$/Barrel .....
NYSE Crude 63.77.....(63.05)
Brent Crude (UK) 70.01 .....(68.96)
Brent Crude (WTI) 63.77(63.05)
NYSE Natural Gas-$/Mmbtu 2.14.....(2.13)
Furnace/ 180 Cst &/bbl 337.79.....(316.37)
Naptha spot /Rs/MT 45170.....(45170)
LSHS spot/ M.T. 36150.....(36150)
Furnace Oil spot/ K.L. 33950.....(33950)
Source:Petroleum Bazaar.com

सर्राफा

Gold .....Mumbai
Standard (99.50 Purity) /10 gms 40678.....(39931)
Pure (99.90 Purity) /10 gms 40842.....(40092)
Silver.999/ kg 47955.....(47330)
Source:India Bullion & Jewellers Association

@SPOT PRICE(MCX, NCDEX & ICEX)

Commodity	Unit	PClose	Price (₹.) Close
29 mm Cotton-Rajkot (N)	1 B	18949.30	18988.75
Alumini-Mumbai (M)	1 K	141.90	143.70
Bajra-Delhi (N)	1 Q	2032.50	2020.00
Bajra-Jaipur (N)	1 Q	2035.75	1994.15
Barley Jaipur (N)	1 Q	2191.90	2217.85
Cardamom-Vand. (I)	1 K	3450.00	3967.00
Castor Seed Disa (N)	1 Q	4294.10	4300.00
Castor Seed-Kadi (N)	X	4232.50	4232.50
Chana Bikaner (N)	1 Q	4413.35	4378.10
Chana Delhi (N)	1 Q	4650.00	4575.00
Chana-Akola (N)	X	4512.50	4450.00
Coriander-Gondal (N)	X	6733.00	6567.00
Coriander-Jaipur (N)	X	7000.00	6850.00
Coriander-Kota (N)	1 Q	7025.75	6878.80
Cotton Seed Oilck Ak (N)	1 Q	2173.55	2135.05
Cotton Seed Oilck Ka (N)	1 Q	2160.40	2080.55
Cotton-Kadi (N)	1 B	18943.35	18985.15
CPO-Kandla (M)	10 K	810.50	799.50
Crude Palm Oil Kandl (N)	10 K	827.15	817.40
Crude Palm Oil-KAKIN (N)	10 K	584.30	807.50
Diamond 0.3 - Surat (I)	1 CT	900.85	920.45
Diamond 0.5-Surat (I)	1 CT	1547.85	1565.40
Diamond 1-Surat (I)	1 CT	3450.55	3479.15
Gold Ahm (M)	10 G	39948.00	40678.00
Gold Guinea-Ahmedaba (M)	8 G	32087.00	32673.00
Gold Petal-Mumbai (M)	1 G	4001.00	4081.00
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (N)	X	7652.10	7342.15
Guar Seed 10 MT-Jodh (N)	1 Q	4101.25	4008.20
Guarseed-Jodhpur (I)	1 Q	4056.00	3975.00
Gur Muzaffar Nagar (N)	40 K	1142.35	1129.25
Isabgulseed-Unjha (I)	1 K	96.90	99.30
Jeera Jodhpur-Jodhpu (N)	X	17000.00	16700.00
Jeera Unjha (N)	1 Q	16216.65	16211.10
Kachi Ghani Must Oil (N)	10 K	755.50	942.20
Kapas Kadi-Kadi (N)	X	1055.65	1043.25
Kapas-Rajkot (N)	X	1054.90	1048.00
Lead Mum (M)	1 K	155.50	154.00
Maize Kharif-Nizamab (N)	X	2040.00	2031.90
Maize Rabi-Gulabbagh (N)	1	2443.90	2447.75
Maize-Erode (N)	X	2064.15	2073.90
Maize-Feed/Ind-Delhi (N)	1 Q	2255.00	2227.50
Maize-Sangli (N)	X	2013.65	2072.70
Masoor Grain Bold In (N)	1 Q	3100.00	5025.00
Moong-Merta City (N)	1 Q	7568.75	7550.00
Mustardseed Alwar (N)	20 K	4829.70	4643.00
Nickel Mumbai (M)	1 K	1037.50	1030.70
Paddy-Basmati-Karnal (I)	1 Q	3220.00	3221.00
Paddy-Basmati-Karnal (N)	X	3300.00	3300.00
Pepper-Ernakulam (I)	1 K	349.60	345.00
Pepper-Kochi (N)	1 Q	35000.00	35000.00
Rape mustards-Patan (I)	20 K	832.00	843.00
Rapeseed Must.Seed (N)	X	2075.00	2050.85
RBD Palm Olein Kakin (N)	10 K	880.00	870.00
Ref Soya Oil Indore (N)	10 K	937.80	922.35
Ref Soya Oil Mum (N)	10 K	936.55	931.30
Ref Soya Oil Nagpur (N)	10 K	956.25	948.75
Rubber-Kochi (N)	1 Q	13100.00	13200.00
Rubber-Kochi/Ernak. (I)	1 Q	13133.00	13200.00
Silver M-Ahemdabad (M)	1 K	47307.00	47941.00
Soy Bean Indore (N)	1 Q	4516.00	4326.00
Soy Bean Kota (N)	1 Q	4370.00	4343.00
Soy Bean Nagpur (N)	1 Q	4494.50	4363.20
Soy Bean-Akola (N)	X	4456.00	4307.00
Soymeal Indore (N)	1 T	36000.00	35500.00
Soyoil-Indore (I)	10 K	918.60	929.00
Steel Long-Ghaziabad (I)	1 T	30080.00	32000.00
Steel Long-MGG (I)	1 T	31200.00	32510.00
Steel Long-Raipur (I)	1 T	28800.00	30320.00
Sugar M Delhi (N)	1 Q	3255.00	3295.00
Sugar M Grade-Kanpur (N)	1 Q	3374.10	3447.60
Sugar M Grade-Kolhap (N)	1 Q	3272.50	3302.50
Sugar M Kolkatta (N)	1 Q	3471.45	3533.35
Sugar M Muzaff (N)	1 Q	3300.00	3328.75
Sugar S-Kolhapur (N)	1 Q	3120.00	3151.25
Turmeric Nizamabad (N)	1 Q	6256.50	6138.65
Wheat Delhi (N)	1 Q	2358.35	2366.25
Wheat Kota (N)	1 Q	2257.50	2260.00
Wheat New Indore (N)	1 Q	2310.00	2320.00
Wheat New Kanpur (N)	1 Q	2190.00	2190.00
Wheat New-Rajkot (N)	1 Q	2325.00	2330.00
Yellow Peas Mum (N)	1 Q	5700.00	5700.00
Yellow Peas-Kanpur (N)	1 Q	2474.50	5600.00
Zinc Mumbai (M)	1 K	183.50	184.60

* as on Jan 03, 20

(M) MCX ,(N) NCDEX & (I) ICEX Spot prices

जिंस वायदा

Name Exchange (Units)

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
DAY SESSION				
दिवस सत्र (सोमवार)				
कृषि जिंस				
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Jan 31	19640, 19780, 19640, 19730	3988	506	17798
Feb 28	19920, 20020, 19920, 20010	519	99	2645
Mar 31	20220, 20220, 20220, 20220	04	1	85
CottonSeed Oil-Akola NCDEX(1 Q)				
Jan 20	2145, 2145, 2075, 2098	25340	1923	40870
Feb 20	2141, 2141, 2105, 2121	41260	2995	61720
Mar 20	2157, 2157, 2127, 2148	3510	321	7280
Apr 20	2180, 2180, 2155, 2167	720	56	2040
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1121, 1123, 1116.5, 1121.5	144	29	848
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1122, 1124.5, 1115.5, 1123.5	977	566	4506
Grains				
Bajra NCDEX(1 Qtl)				
Jan 20	2030, 2030, 2025, 2025	110	7	110
Guar Seed 10 NCDEX(1 Qtl)				
Jan 20	4098, 4146, 4036, 4078	21850	2770	38950
Feb 20	4150, 4150, 4082, 4126	38375	4430	63485
Mar 20	4170, 4174, 4140, 4166	215	22	715
Oil and Oilseeds				
CastorSeed New-Disa NCDEX(1 Qtl)				
Jan 20	4220, 4240, 4156, 4228	5975	503	18350
Feb 20	4230, 4268, 4194, 4262	5995	589	18245
Mar 20	4182, 4258, 4180, 4226	350	39	7025
Apr 20	4200, 4230, 4200, 4214	925	98	2550
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Jan 31	809.2, 812.7, 789.2, 794.3	29350	2175	37960
Feb 28	810, 814.6, 792.4, 797	14980	1036	21240
Mar 31	807, 807, 795.5, 799.8	270	24	810
Mentha Oil MCX(1 K)				
Jan 31	1288.1, 1295, 1281, 1286.1	124.56	271	235.44
Feb 28	1300.4, 1300.4, 1293, 1294.5	4.32	12	21.24
Mustard Seed Rape Oil NCDEX(1 Q)				
Jan 20	4605, 4605, 4476, 4483	8650	576	12860
Feb 20	4600, 4602, 4478, 4485	13620	979	9580
Apr 20	4501, 4501, 4413, 4425	8200	598	10480
May 20	4470, 4480, 4436, 4446	470	38	900
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Jan 20	933.6, 933.6, 905.8, 912.4	19830	2187	25385
Feb 20	929.6, 931.4, 904.2, 910	34690	3404	48865
Mar 20	922, 922, 898.2, 901.4	2995	393	23155
Apr 20	917.8, 917.8, 898, 900.2	395	67	2655
Soyabean Indore NCDEX(1 Q)				
Jan 20	4340, 4344, 4184, 4190	56395	5496	65040
Feb 20	4362, 4368, 4208, 4210	91875	9346	190030
Mar 20	4380, 4380, 4226, 4236	31960	3425	87555
Apr 20	4412, 4412, 4262, 4280	4755	589	15555
May 20	4450, 4452, 4320, 4358	840	124	1540
Others				
GuarGum 5T-Jodhpur NCDEX(1 Qtl)				
Jan 20	7398, 7425, 7231, 7306	8070	1180	15320
Feb 20	7490, 7494, 7334, 7405	15775	2340	52630
Mar 20	7551, 7551, 7440, 7505	775	101	3280
Pulses				
Chana-Bikaner NCDEX(1 Qtl)				
Jan 20	4490, 4491, 4431, 4461	15150	1017	21740
Mar 20	4444, 4444, 4380, 4401	8220	668	15180
Apr 20	4425, 4425, 4389, 4401	790	72	1270
Spices				
Cardamom MCX(1 K)				
Jan 15	4051.1, 4185, 4000, 4045.3	1	10	5.3
Feb 14	4093.5, 4128, 3932, 4079.4	3.6	27	6.6
Coriander-Kota NCDEX(1 Q)				
Jan 20	6635, 6664, 6405, 6514	2270	203	7040
Apr 20	7010, 7149, 6829, 6837	3390	317	7730
Jeera Unjha NCDEX(1 Q)				
Jan 20	16090, 16200, 16070, 16125	651	190	1182
Mar 20	15565, 15790, 15565, 15705	543	169	1308
Apr 20	15280, 15455, 15280, 15335	36	12	456
Turmeric Nizamabad NCDEX(1 Q)				
Mar 20	6492, 6504, 6276, 6278	2410	424	5955
Apr 20	6402, 6410, 6184, 6192	1075	199	4340
May 20	6450, 6480, 6414, 6414	15	3	45
धातु				
Metal- non ferrous				
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Jan 31	139.25, 140.95, 137.95, 140.3	5300	3374	6072
Feb 28	138.35, 140.35, 137.5, 139.9	272	249	1089
Feb 28	1021, 1027.5, 1016.8, 1017.3	208.5	134	196.5
Zinc Mini MCX(1 K)				
Jan 31	180.45, 182.4, 180.45, 181.4	18920	11275	18632
Feb 28	181, 182.4, 180.5, 181.6	1002	786	3566
Mar 31	182.5, 182.5, 182.5, 182.5	1	1	1
Metal- precious				
Gold MCX(10 G)				
Feb 05	40250, 41096, 40250, 40879	11.69	9726	15.14
Apr 03	40480, 41300, 40480, 41097	1.14	962	8.04
Gold Guinea MCX(8 G)				
Jan 31	32000, 32800, 32000, 32588	0.01	606	0.01
Feb 28	31971, 32799, 31971, 32599	0	200	0
Mar 31	32628, 32701, 32350, 32436	0	12	0
Gold Mini MCX(10 G)				
Feb 05	40250, 41049, 40250, 40841	1.65	13595	1.28
Mar 05	40378, 41144, 40378, 40943	0.16	1238	0.25
Apr 03	41150, 41200, 40946, 41083	0	32	0
Gold Petal MCX(1 Gm)				
Jan 31	3999, 4098, 3999, 4063	0.01	1708	0.01
Feb 28	4000, 4098, 4000, 4070	0	526	0
Mar 31	4099, 4099, 4060, 4072	0	11	0
Silver MCX(1 K)				
Mar 05	48300, 48660, 48236, 48368	379.32	10261	339.87
May 05	49000, 49160, 48775, 48897	3.24	106	12.27
Silver Micro MCX(1 K)				
Feb 28	47680, 48687, 47680, 48383	42.32	28782	27.18
Apr 30	48391, 49199, 48391, 48927	2.73	1917	3.43
Jun 30	50000, 50000, 49340, 49553	0.01	8	0.04
Silver Mini MCX(1 K)				
Feb 28	47549, 48690, 47549, 48387	117.58	18797	57.69
Apr 30

जेएनयू हिंसा पर बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जेएनयू प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की जिसमें कुलपति नहीं हुए शामिल। गृह मंत्री शाह बोले कांग्रेस और आप ने दिल्ली को दंगे की आग में झुलसाने का पाप किया है

अर्चिस मोहन

देश की राजधानी में मौजूद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के परिसर में रविवार की रात हुई हिंसा की निंदा देश भर में हो रही है और इस घटना की न्यायिक जांच की मांग के साथ-साथ विश्वविद्यालय के कुलपति को बर्खास्त करने की मांग भी बढ़ी है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) पर 'देश की राजधानी में दंगे की आग में भड़काने' का आरोप लगाया। रविवार की शाम कुछ नकाबपोश गुंडों ने जेएनयू में छात्रों और शिक्षकों पर हमला किया जिसके खिलाफ सोमवार को देश भर में विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गया और आने वाले दिनों में ऐसे और प्रदर्शन होने की संभावना जताई गई। विपक्षी दलों ने यह आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) इस हिंसा के पीछे थी और केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली दिल्ली पुलिस ने समय पर हिंसा रोकने के लिए हस्तक्षेप किया।

विश्वविद्यालय परिसर में हुई हिंसा में तीन दर्जन छात्र घायल हो गए जिनमें जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आइशी घोष भी शामिल हैं। घोष ने यह आरोप लगाया कि यह एक संगठित हमला था और संघ से संबद्ध कुछ प्रोफेसर हिंसा को बढ़ावा दे रहे थे। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को कहा कि उन्होंने पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीओर) को किये गए कॉल पर और कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिये पेशेवराना अंदाज में काम किया। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता मंदीप सिंह रंधावा ने कहा कि जेएनयू की आंतरिक सुरक्षा विश्वविद्यालय प्रशासन के पास है। उन्होंने कहा कि अपराध शाखा को कुछ अहम सुराग मिले हैं और उन पर काम किया जा रहा है।

जेएनयू परिसर के बाहर सोमवार को मीडियाकर्मियों, पुलिस और छात्रों का हुजूम *फोटोः दलीप कुमार*

दिल्ली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि कांग्रेस और आप ने युवाओं और दिल्ली के लोगों को गुमराह करते हुए देश की राजधानी में उन्हें दंगे की आग में झुलसाने का पाप किया है और प्रदेश की जनता उनसे इसका हिसाब मांगेगी । शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी एवं प्रियंका गांधी वाड्रा संशोधित नागरिकता कानून पर झूठ बोल कर अल्पसंख्यकों को गुमराह कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जेएनयू परिसर में हुई हिंसा की निंदा करते हुए कहा कि देश के युवाओं पर भयावह एवं अप्रत्याशित ढंग से हिंसा की गई और ऐसा करने वाले गुंडों को सत्तारूढ़ मोदी सरकार की ओर से उकसाया गया है। उन्होंने जेएनयू घटना की स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग भी की। वहीं माकपा प्रमुख सीताराम येचुरी ने जेएनयू के कुलपति को बर्खास्त करने की मांग की।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कहा कि राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) भारत को बांटने के लिए मौजूदा सरकार की तरफ से लाई गई शरारतपूर्ण और भयावह योजना है। उन्होंने यह आरोप लगाया कि एनआरसी-नागरिकता संशोधन कानून और एनपीआर संघ -भाजपा की देश का बंटवारा करने और 'हिंदू राष्ट्र' के एजेंडे का हिस्सा है। इस बीच मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने जेएनयू प्रशासन से जुड़े लोगों से मुलाकात की। जेएनयू के कुलपति एम जगदीश कुमार इस बैठक में शामिल नहीं हुए। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने सोमवार को कहा कि शैक्षणिक संस्थानों को 'राजनीतिक अड्डा' नहीं बनने दिया जा सकता और उन्होंने जेएनयू हमले के गुनहगारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संकल्प लिया।

उद्योग जगत भी हमले से नाराज

कई उद्योगपतियों ने जेएनयू हिंसा की निंदा करते हुए दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही देश के शीर्ष उद्योगपतियों ने रविवार रात जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में हुई हिंसा पर चिंता जताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। कई उद्योगपतियों आनंद महिंद्रा, हर्ष मारीवाला और किरण मजूमदार शॉ ने कहा कि इस तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस घटना के दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। मैरिको के चेयरमैन हर्ष मारीवाला ने ट्वीट किया, 'अहिंसा की धरती से हमें इस तरह की हिंसा की घटना देखने को मिली। कल शाम आई खबरों से मुझे काफी दुख हुआ है।' इसी तरह की राय जताते हुए महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने रविवार शाम को ट्वीट किया, 'यह मायने नहीं रखता कि आपकी राजनीति क्या है, विचारधारा क्या है। आपका किसमें विश्वास है। यदि आप भारतीय हैं तो ऐसे हथियारबंद कानून तोड़ने वाले गुंडों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिन्होंने भी जेएनयू पर हमला किया है उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए।' *एजेंसियां*

भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मुहिम उद्योग पर हमला नहीं: मोदी

नई दिल्ली में किर्लोसकर ब्रदर्स के 100वें स्थापना समारोह में मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि कुछ भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई को उद्योग जगत पर हमले के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि उनकी सरकार का इरादा भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसना है ना कि उद्योग जगत को नुकसान पहंचाना। उन्होंने कहा कि देश के उद्योग जगत में इसे लेकर कोई भ्रम या भय नहीं होना चाहिए।

नई दिल्ली में किर्लोसकर ब्रदर्स के 100वें स्थापना समारोह पर मोदी ने कहा कि सरकार ने उद्योग जगत को एक पारदर्शी वातावरण में बिना किसी भय के धन सृजन करने का अवसर मुहैया कराने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार उद्योगों को कानूनों के जंजाल से छुटकारा दिलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में उनकी सरकार ने ईमानदारी से काम किया है।

मोदी ने कहा कि कर प्रणाली में पादर्शिता, दक्षता एवं जवाबदेही लाने का प्रयास लगातार होते रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर विभाग में मानव हस्तक्षेप कम से कम रखने की दिशा में काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कंपनियों को निवेश हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कॉर्पोरेट कर में कमी की गई है।

उन्होंने उद्योग जगत से निराशा से बाहर निकलने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के हरेक कोने में कारोबार पहुंचाने के लिए उनकी सरकार भारतीय उद्योग जगत के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था का आकार 5 लाख करोड़ डॉलर करना महज एक पड़ाव होगा और लक्ष्य तो और भी ऊंचा है। *एजेंसियां*

पोर्नोग्राफी पर सोशल मीडिया अधिकारियों से सवाल

नेहा अलावधी

सोशल मीडिया पर पोर्नोग्राफी के चिंताजनक मसले तथा बच्चों और समाज पर इसके व्यापक प्रभाव पर चर्चा के लिए राज्यसभा की एक तदर्थ समिति ने आज गूगल, ट्विटर, शेयरचैट और एचईआरडी फाउंडेशन के अधिकारियों से मुलाकात की। इन अधिकारियों से पूछा गया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी (बच्चों से संबंधित अश्लीलता) रोकने के लिए उनकी कंपनियों ने क्या उपाय किए हैं।

बैठक में मौजूद एक सूत्र के अनुसार समिति के सदस्यों ने प्रौद्योगिकी कंपनियों से उनसे संबंधित प्लेटफार्मों पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर अंकुश लगाने के तरीकों के बारे में पूछा है। बैठक में गूगल के इंडिया मैनेजर (सार्वजनिक नीति) राहुल जैन, ट्विटर इंडिया की नीति प्रमुख महिमा कौल, शेयरचैट के सार्वजनिक नीति और नीतिगत संचार प्रमुख बर्गेस मालु तथा एचईआरडी फाउंडेशन के अमोल देशमुख और सुचेता गुप्ता ने भाग लिया।

इस चर्चा के संबंध में जानकारी रखने वाले एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि कंपनी के अधिकारियों में से एक ने सुझाव दिया है कि अमेरिका में बच्चों के ऑनलाइन गोपनीयता संरक्षण अधिनियम (सीओपीपीए) की तर्ज पर कुछ प्रावधान किया जाए। यह कानून इंटरनेट सेवाओं और वेबसाइटों के संचालकों द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जानकारी का संग्रह और उपयोग नियंत्रित करने के लिए तैयार किया गया है।

बढ़ी सक्रियता

- अन्नाद्रमुक सांसद विजिला सत्यनाथ ने संसद में उठाया मुद्दा जिसके बाद बनी तदर्थ समिति
- विनय सहसबुद्धे, जया बच्चन, राजीव चंद्रशेखर, एम वी राजीव गौड़ा, रूपा गांगुली, तिरुचि शिव इसके सदस्यों में शामिल
- पैनल ने कहा कि यह ट्राई, सीईआरटी-ईन, तकनीकी कंपनियों और नागरिक समाज समूहों से करेगा मुलाकात
- समिति अपनी रिपोर्ट जनवरी के मध्य तक सौंपेगी
- समिति इसके विधायी समाधान का विकल्प भी ढूंढ रही है

इस अधिकारी ने अमेरिका में संघीय व्यापार आयोग की तरह एक निकाय होने का भी सुझाव दिया जो ऑनलाइन मीडिया प्लेटफार्मों को नियंत्रित करता है। गूगल से उसके सर्चिंग प्लेटफॉर्म और इस प्लेटफॉर्म पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछा गया है। सामाजिक मसलों के अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने वाले एचईआरडी फाउंडेशन ने अपराधियों पर निगारनी रखने के लिए ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करने समेत चाइल्ड पोर्नोग्राफी की समस्या से से निपटने को लेकर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश की अध्यक्षता वाली इस समिति ने 20 दिसंबर को फेसबुक, टिकटॉक और अन्य सरकारी प्रतिनिधियों से इसी विषय पर उनके विचार जानने के लिए मुलाकात की थी। उस बैठक में फेसबुक ने समिति को मलेशियाई संचार एवं मल्टीमीडिया आयोग (एमसीएमसी) के साथ अपनी साझेदारी के बारे में अवगत कराया था। टिकटॉक से अश्लील सामग्री फैलाने के लिए मंच के दुरुपयोग के बारे में पूछा गया था।

बंगाल में भाजपा नेताओं में बढ़ी असंतुष्टि

पार्टी के कुछ नेता बोस की तरह मुखर नहीं हैं लेकिन वे नागरिकता कानून को लेकर संशय में हैं क्योंकि उन्हें इस बात की आशंका है कि इसका राज्य में भाजपा के भविष्य पर असर पड़ेगा

अभिषेक रक्षित

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) न केवल नागरिक समाज के विभिन्न वर्गों बल्कि विपक्षी दलों तथा पश्चिम बंगाल में पार्टी के मध्यम कतार के नेताओं के निशाने पर भी आ गई है। राज्य में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हिंसा के साथ प्रदर्शन हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) को राज्य में किसी भी कीमत पर राज्य में लागू न करने की प्रतिबद्धता जताई है। वह देश के दूसरे दलों के साथ भी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ तालमेल बनाने की कोशिश में हैं।

दूसरी तरफ राज्य में भाजपा नेता भी नागरिकता संशोधन कानून के प्रति दबे सुर में ही आलोचना कर रहे हैं। भाजपा राज्य इकाई के उपाध्यक्ष चंद्र कुमार बोस इस कानून के मौजूदा स्वरूप की आलोचना को लेकर सबसे ज्यादा मुखर रहे हैं। उनका कहना है, 'देश किसी दल की राजनीति से ऊपर है। आखिर मैं कैसे चुप रह सकता हूं जब मैं यह देख पा रहा हूं यह गलत हो रहा है।'

सुभाष चंद्र बोस (नेताजी) के परिवार से ताल्लुक रखने वाले बोस कहते हैं कि नागरिकता संशोधन कानून मौजूदा स्वरूप में देश की धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के खिलाफ है। उन्होंने कहा, 'मैं नागरिकता कानून के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन मौजूदा स्वरूप में यह मुसलमानों के खिलाफ है। मेरा यह मानना है कि यह समुदाय देश के इतिहास और विरासत का अहम हिस्सा है और इन्हें भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। नेताजी अगर होते तो वह इस कानून को कभी पारित होने की इजाजत नहीं देते।'

भाजपा 'अभिनंदन यात्रा' के जरिये अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए देश के लोगों से संपर्क कर नागरिकता संशोधन कानून के फायदे बताने की कोशिश कर रही है

पार्टी के दूसरे नेता बोस की तरह इतने मुखर नहीं हैं लेकिन वे सवाल करते हैं कि इस कानून की वजह से राज्य में भाजपा की संभावनाओं पर क्या असर होगा। ऐसे वक्त में जब भाजपा ने राज्य में अपना दखल बढ़ाना शुरू किया था लेकिन नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी की वजह से पार्टी की संभावनाएं क्षीण नजर आ रही हैं। पिछले साल आम चुनाव के दौरान भाजपा का राज्य में अच्छा प्रदर्शन रहा और पार्टी ने राज्य की 42 सीट में से 18 हासिल करते हुए 40.25 फीसदी वोट हिस्सेदारी पा ली। तृणमूल को 22 सीट मिलीं और पार्टी की वोट हिस्सेदारी 43.28 फीसदी रही।

नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी की वजह से बंगाल में भाजपा के भविष्य पर लगे सवालिया निशान

हालांकि विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। पार्टी को न केवल अपने मजबूत गढ़ खड़गपुर सदर को गंवाना पड़ा बल्कि वह दो अन्य सीटों पर भी तृणमूल का मुकाबला नहीं कर पाई। कुछ हारने वाले उम्मीदवारों और पार्टी के मझोले क्रम के नेतृत्व ने भी चुनाव में खराब प्रदर्शन के लिए नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को जिम्मेदार ठहराया। बोस का मानना है कि अगर इस वक्त पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होते हैं तो भाजपा को बड़ी हार का सामना करना पड़ सकता है। राजनीतिक विश्लेषक सव्यसाची बसु रॉय चौधरी कहते हैं, 'भाजपा के नेतृत्व के सुर में भी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भ्रम वाली स्थिति है जिसकी वजह से पार्टी की संभावनाओं को नुकसान हो रहा है।'

तृणमूल पार्टी में भी मझोले स्तर के नेता भी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उनके हाथों से मुस्लिम वोट खिसक रहे हैं और इस समुदाय के समर्थन के बगैर राज्य की सत्ता में वापस आना मुश्किल है क्योंकि इन मतदाताओं की तादाद 30 फीसदी है। राजनीतिक विश्लेषक विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, 'पश्चिम बंगाल के हिंदू भी इस बात को लेकर चिंतित हैं क्योंकि असम में 12 लाख हिंदू एनआरसी से बाहर हैं।'

इसके अलावा भाजपा के असंतुष्ट नेताओं का भी मानना है कि जब तक राज्य सरकार केंद्र के साथ सहयोग नहीं करती है तब तक नागरिकता संशोधन कानून पर अमल नहीं किया जा सकता। राज्य के एक असंतुष्ट भाजपा नेता कहते हैं, 'संसद में कई कानून पारित हुए हैं लेकिन क्या सबको सफलतापूर्वक अमलीजामा पहनाया गया है? संघीय संरचना में किसी भी कानून के ठीक तरह से लागू करने के लिए राज्य सरकार का सहयोग जरूरी है।' पार्टी में असंतोषजनक स्थिति बनने के बावजूद भाजपा ने विपक्ष की रणनीति का विरोध करने का फैसला किया है और यह लोगों को नागरिकता संशोधन कानून के फायदे गिना रही है।

पार्टी 'अभिनंदन यात्रा' के जरिये अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही है और देश भर में ऐसी रैलियों का आयोजन कर रही है। पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष दिलीप घोष राज्य में हो रही हिंसा में कथित तौर पर शामिल होने और अतिवादी रुख अपनाने के लिए ममता बनर्जी के प्रशासन और तृणमूल की आलोचना कर रहे हैं और उनके मुताबिक यह देश के हितों के खिलाफ है।

भाजपा के मुताबिक देश के नागरिकों को नागरिकता कानून को लेकर चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि किसी को भी राष्ट्रीयता साबित करने के लिए सामान्य आधिकारिक दस्तावेज की जरूरत होगी। हालांकि इसके लिए जरूरी दस्तावेज की सूची को अंतिम रूप देना बाकी है।

महानगरों की महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा खाती हैं चीनी

संजीव मुखर्जी

महानगरों में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं औसतन ज्यादा मात्रा में चीन खाती हैं। सभी महानगरों में से मुंबई में रहने वाले लोग चीनी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर)-राष्ट्रीय पोषण संस्थान (एनआईएम) ने ऐसा सर्वेक्षण कराया जिसे इंटरनैशनल लाइफ साइंसेज इंस्टीट्यूट-इंडिया (आईएलएसआई-इंडिया) ने प्रायोजित किया था।

नैशनल न्यूट्रिशन मॉनीटरिंग ब्यूरो (एनएनएमबी) ने वर्ष 2015-16 के दौरान 16 बड़े राज्यों से आहार संबंधी आंकड़े जुटाए और निष्कर्ष निकालने के लिए उसकी दोबारा कोडिंग रेसिपी के आधार पर और महानगरों के आधार पर की। इस सर्वे का निष्कर्ष हाल में ही जारी किया गया था। इसमें यह अंदाजा मिला कि मेट्रो शहरों की महिलाएं रोजाना 20.2 ग्राम चीनी इस्तेमाल करती हैं जबकि पुरुष 18.7 ग्राम चीनी प्रतिदिन खाते हैं।

इस सर्वे में यह पता चला कि महानगरों में अतिरिक्त चीनी का उपभोग आईसीएमआर द्वारा निर्धारित 30 ग्राम प्रतिदिन के स्तर से भी कम है। महानगरों में अतिरिक्त चीनी का कुल उपभोग 19.5 ग्राम प्रतिदिन है। इन शहरों के कुल ऊर्जा उपभोग में अतिरिक्त चीनी (ऐडेड शुगर) की मात्रा महज 5.1 फीसदी है। प्राकृतिक तौर पर जिन चीजों में अनाज और जौ-बाजरा के जरिये और दूध आधारित व्यंजनों के जरिये चीनी की खपत ज्यादा होता है।

आहार विशेषज्ञ इस अतिरिक्त चीनी को शुगर कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं जिसे खाना बनाने के दौरान खाद्य और पेय पदार्थ में डाला जाता है। इस प्रकार की चीनी को रसायनिक तौर पर प्राकृतिक चीनी से अलग नहीं किया जा सकता है लेकिन ऐडेड शुगर का इस्तेमाल मीठे खाने की पहचान के तौर पर किया जाता है। इस सर्वेक्षण के मुताबिक घरेलू औरतें ज्यादा मात्रा में चीनी का उपभोग करती हैं और यह मात्रा रोजाना 21.3 ग्राम रहती है जबकि पेशेवर महिलाएं 15.4 ग्राम चीनी का इस्तेमाल रोजाना करती हैं। मजदूर वर्ग भी पेशेवर लोगों के मुकाबले ज्यादा करीब 18.3 ग्राम चीनी का इस्तेमाल रोजाना करते हैं। इस अध्ययन से यह भी अंदाजा मिला कि पेशेवर लोग सेहत के लिहाज से चीनी के बुरे असर को लेकर ज्यादा जागरुक हैं।

स्रोतः देश के महानगरों की शहरी आबादी में अतिरिक्त चीन के उपभोग के आकलन से जुड़ी रिपोर्ट

अतिरिक्त चीनी का औसत उपभोग

ग्राम प्रतिदिन में

मुंबई	26.3
अहमदाबाद	25.9
दिल्ली	23.2
बेंगलूरु	19.3
कोलकाता	17.1
चेन्नई	16.1
हैदराबाद	15.5

इस अध्ययन में यह भी पाया गया कि महानगरों में कम आमदनी वाले समूह के लोग ज्यादा मात्रा में चीनी का उपभोग करते हैं और यह मात्रा कम से कम 19.4 ग्राम रोजाना है। वहीं ज्यादा आमदनी वर्ग के लोग रोजाना 18.8 ग्राम चीनी का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कम बढ़े-लिखे लोग भी ज्यादा शिक्षित वर्ग की तुलना में अधिक चीनी का उपभोग करते हैं। हैरानी की बात यह है कि इस अध्ययन में इस बात का अंदाजा भी लगा है कि सवर्ण जाति के लोग ज्यादा मात्रा में चीनी की खपत करते हैं और वे 20.6 ग्राम चीनी प्रतिदिन लेते हैं। वहीं अनुसूचित जाति के लोग 17.3 ग्राम चीनी का उपभोग रोजाना करते है।

इस सर्वेक्षण में आयु वर्ग के लिहाज से भी चीनी के उपभोग का पता किया गया और सामान्यतौर पर वयस्क और बुजुर्ग, किशोरों के मुकाबले चीनी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। बुजुर्गों (60 साल से अधिक) में चीनी की खपत सबसे ज्यादा 20.5 ग्राम प्रतिदिन है जबकि 36-59 उम्र वर्ग में चीनी की खपत 20.3 ग्राम प्रतिदिन है। किशोर रोजाना 19.9 ग्राम चीनी उपभोग करते हैं जबकि युवा (18-35 साल) 19.4 ग्राम चीनी का इस्तेमाल रोजाना करते हैं। स्कूल और प्री-स्कूल जाने वाले बच्चे रोजाना 17.6 ग्राम और 15.6 ग्राम अतिरिक्त चीनी का इस्तेमाल रोजाना करते हैं।